04 - समता, सामाजिक न्याय, विकास व हिंदुत्व का परिणाम

05 - क्या भारत को चाहिए एक व्यापक 'प्रदूषण कर'?

A Daily News Magazine

इंदौर

शनिवार, 22 नवम्बर, 2025

06 - पीएम आवास के पहले फेज में शहरी सीमा में स्वीकृत हुए...

07 - एसआईआर प्रक्रिया किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 59, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

चुनाव बहिष्कार करके विपक्ष को क्या हासिल होगा?

पंकज श्रीवास्तव

क्या चुनाव बहिष्कार विपक्ष के लिए फायदेमंद रणनीति है या राजनीतिक आत्मघाती कदम? जानिए बहिष्कार के संभावित लाभ, जोखिम, जनता पर असर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसके दूरगामी परिणामों का विस्तृत विश्लेषण।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली अभूतपूर्व सफलता ने कई सवाल उठा दिये हैं। इसके पीछे SIR के नाम पर हुई वोट चोरी से लेकर करोड़ों महिलाओं को दस हज़ार रुपये की खुली रिश्वत को वजह बताया जा रहा है। आरोप है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के मातहत की तरह काम कर रहा है और इस परिस्थिति को जनता के बीच मुद्दा बनाने का ऐतिहासिक दायित्व रखने वाला मीडिया सरकार की गोदी में बैठकर बिस्कुट खा रहा है। ऐसे में जनता की चेतना को झिंझोड़ने के लिए विपक्ष को चुनाव बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ना सरकार को वैधता देना है। लेकिन क्या सचमुच बहिष्कार से विपक्ष को धार मिलती है?

18 नवंबर को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक हुई। जिन 12 राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चल रहा है, उनके प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों को बुलाया गया था। कांग्रेस का आरोप है कि SIR के नाम पर लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं- खासकर उन इलाकों में जहाँ विपक्ष मजबूत है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा- 'अगर निर्वाचन आयोग इसे नजरअंदाज करता है तो यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, संलिप्तता है।' कांग्रेस दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में इसी मुद्दे पर बड़ी रैली करने जा रही है।

इसी बीच कई विचारकों ने विपक्ष के चुनाव लड़ने को बेमानी बताते हुए बहिष्कार को ज़रूरी बताया है। इनमें एक हैं आनंद तेलतुम्बड़े - आईआईटी खड़गपुर के पूर्व प्रोफेसर, डॉ.आंबेडकर के परिवार से रिश्ता रखने वाले लेखक और भीमा-कोरेगांव केस में ढाई साल जेल काट चुके मानवाधिकार कार्यकर्ता। स्क्रोल में छपे उनके लेख का शीर्षक ही सब बता देता है - 'विपक्ष का बिहार भ्रम और लोकतंत्र का भ्रम।' वे लिखते हैं कि जब चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट, ईवीएम, मीडिया - सब 'कैप्चर' हो चुके हों, तो चुनाव लड़ने से सत्ता को सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है - 'देखो, लोकतंत्र जिन्दा है।' उनका कहना है कि असली लड़ाई अब सड़क पर और संस्थाओं को मुक्त कराने की है।

दूसरी आवाज और भी चौंकाने वाली है। मशहूर अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर- जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं - ने भी यही बात कही। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा पर करीब 80 सीटें धांधली से जीतने का आरोप लगाया था। बिहार नतीजों के बाद उनका मानना है कि विपक्ष को संसद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सड़कों पर उतरना चाहिए। चुनाव लड़ते रहने से सत्ता और मजबूत होती है।

हमारे पड़ोस में दो देश हैं जिन्होंने बहिष्कार को बार-बार आजमाया है। बांग्लादेश में 1986 और 1988 में खालिदा जिया की बीएनपी ने सैन्य शासक इरशाद के खिलाफ चुनाव का बहिष्कार किया। नतीजा सकारात्मक रहा - 1990 में जनांदोलन ने जनरल इरशाद को सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन बाद के प्रयोग उलटे पड़े। 2014 और 2024 में बीएनपी ने शेख हसीना के खिलाफ बहिष्कार किया। दोनों बार अवामी लीग को सारी सीटें मिलीं, सत्ता और मजबूत हुई। 2024 में मतदान प्रतिशत सिर्फ 40 प्रतिशत रहा, फिर भी हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बनीं। आखिरकार उनकी सत्ता गयी भी तो छात्र आंदोलन से गयी, बहिष्कार से नहीं।

पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सेना के दबाव को देखते हुए चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने निर्दलीय लड़ा। उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन सत्ता शहबाज शरीफ की गोद में बैठ गई। बहिष्कार होता तो शायद पीटीआई आज और हाशिये पर होती। फ़िलहाल नेशनल असेंबली में उसके तमाम सदस्य हैं।

दुनिया भर में हुए शोध भी यही कहते हैं। ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट के 2016 के अध्ययन में 171 चुनाव बहिष्कार के मामलों का विश्लेषण किया गया। निष्कर्ष था - ज्यादातर मामलों में बहिष्कार करने वाली पार्टी को ही नुकसान हुआ। स्वीडन के वी-डेम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता भी कहते हैं - दुनिया में सिर्फ 3-5 प्रतिशत बहिष्कार ही सफल हुए, वो भी तब जब उसके साथ बड़ा जनआंदोलन और अंतरराष्ट्रीय दबाव रहा हो। अकेला बहिष्कार ज्यादातर विपक्ष को खत्म कर देता है।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं अब खुलकर बोल रही हैं कि भारत का लोकतंत्र गहरे संकट में है।

Economist Intelligence Unit (EIU) की 2024 के 'डेमोक्रेसी इंडेक्स' में भारत 167 देशों में 41वें स्थान पर है। 2014 में 27वें नंबर पर थे। स्कोर 7.18 - यानी भारत 'फ्लॉड डेमोक्रेसी' या लंगड़ा लोकतंत्र कहा जा सकता है।

स्वीडन का V-Dem इंस्टीट्यूट और भी सख्त है। 2024 की रिपोर्ट में भारत को 'इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी' कहा गया है - यानी चुनाव तो होते हैं, लेकिन नतीजे नियंत्रित और प्रभावित। रैंक 179 देशों में 100वाँ। रिपोर्ट चेताती है कि भारत 'क्लोज्ड ऑटोक्रेसी' बनने के करीब है।

कई विचारक मानते हैं कि आज का संकट सिर्फ एक पार्टी या एक नेता का नहीं है। यह पूंजीवाद के मौजूदा संकट का नतीजा है। दुनिया भर के कई देशों में चुनकर आये नेताओं में तानाशाही की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गयी है। वे लोकतंत्र को विकास में बाधा मान रहे हैं। भारत में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने दिसंबर 2020 में जो कहा था, वह आज भी गूंजता है- "Tough reforms are very difficult in the Indian conte&t, we are too much of a democracy." यानी कड़े सुधार करने में 'ज्यादा लोकतंत्र' बाधा बनता है। बयान पर बवाल हुआ, लेकिन काम उसी दिशा में हुआ।

राहुल गांधी बार-बार 'क्रोनी कैपिटलिज्म' यानी याराना पूँजीवाद की बात करते हैं। यह वह तंत्र है जिसमें चुनिंदा पूंजीपतियों के लिए ही सरकार काम करती है, बदले में पार्टी को अकूत धन मिलता है। इसी वजह से चुनाव इतने महँगे कर दिये गये हैं कि आम आदमी या छोटी पार्टियाँ चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकतीं। बिहार में चुनाव से ठीक पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपये डाले गए। पहले ऐसे मामलों में चुनाव आयोग तुरंत रोक लगाता था, इस बार चुप रहा। मीडिया ने भी इसे मुद्दा नहीं बनाया।

यानी सत्ता और पूंजी का गठजोड़ इतना मजबूत हो गया है कि उसे अब 'लोकतंत्र की बाधा' नहीं चाहिए। यानी जनता को तमाशबीन बना दिया गया है।

इसके बावजूद विपक्ष के लिए बहिष्कार कोई समाधान नहीं। संसद अगर सर्द पड़ जाए तो सड़क गर्माना ही एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन सड़क पर सिर्फ विपक्ष नहीं, आम जनता को भी उतरना होगा।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बीएसएफ जवानों के शौर्य से अपना देश सुरक्षित

● गुजरात के कच्छ में 'सिंदूर वन' के पास गरजे अमित शाह ● भारत-पाकिस्तान युद्ध का किया जिक्र,बीएसएफ की तारीफ

अहमदाबाद/कच्छ (एजेंसी)। भारतीय सीमा सुरक्षा (बीएसएफ) के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि आने वाला साल बीएसएफ जवानों के परिवारों को समर्पित रहेगा। उन्होंने कहा कि आज देश बीएसएफ के शौर्य की वजह से सुरक्षित है। अमित शाह ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा हो, एंटी-टेरर अभियान हों या आपदाओं में राहत-बचाव, बीएसएफ के जवानों ने हमेशा शौर्य और पराक्रम की मिसाल पेश की है। अमित शाह ने बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आज भुज (गुजरात) में बल के वीर बलिदानियों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। देश अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा।

1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध का किया जिक्र

गृह मंत्री अमित शाह ने उसी जगह पर बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हुआ था। अब उस स्थान पर सिंदूर वन बना चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की याद में खाली पड़ी भूमि पर सिंदूर वन विकसित किया गया है। कच्छ के भुज में इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि देश साक्षी है, कच्छ के लोगों ने कई सारे युद्धों में सेना और बीएसएफ के साथ रन वे रिपर कर सुरक्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। गौरतलब हो कि 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध ने पाकिस्तान ने भुज हवाई अड्डे की पट्टी को नुकसान पहुंचाया था लेकिन कच्छ की वीर महिलाओं ने इसे रातोंरात ठीक कर दिया था। इस पर बॉलीवुड भुज द प्राइड फिल्म बनी है।

चुन-चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे

अमित शाह ने कहा,मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक-एक घुसपैठिए को चुन-चुन कर बाहर निकालेंगे, यह हमारा प्रण है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया देश और हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए है। बिना किसी पार्टी का नाम लिए, शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को हटाने के इस अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिहार चुनाव में जनता एनडीए को पहले ही जनादेश दे चुकी है। शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को खत्म करने के अभियान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को साफ करने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज, मैं देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वे चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही प्रक्रिया का पूरा समर्थन करें।

शरद की सुबह

इश्क़ किसी से कर
बैठी अनजाने में
और फिर सांसे भरनी
पड़ीं हर्जाने में
कब से लगी हूँ खुद को
ये समझाने में
एक ही हिचकी लगती
है मर जाने में
सच तो ये है धूप का
बिल्कुल हाथ नहीं
सारी ख़ता फूलों की है
मुरझाने में
ख्वाबों की इक लाश
अचानक बोल उठी
कितनी देर लगाओगे
दफ़नाने में
देखो किसने आज
दरीचे खोल दिए
धूप उतर कर आई है
तहखाने में
शहरों को आबाद
करेंगे हम सरिता
क़ैस और लैला
घूमेंगे वीराने में।

– सरिता जैन

मेक्सिको की फातिमा बोश बनीं मिस यूनिवर्स

● बेवकूफ कहे जाने पर सेरेमनी छोड़कर चली गई थी

मेक्सिको सिटी (एजेंसी)। मेक्सिको की फातिमा बोश फर्नांडेज ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब हासिल कर लिया है। फातिमा बोश 25 साल की हैं। भारत की तरफ से गई मणिका विश्वकर्मा टॉप-30 में पहुंचीं, लेकिन टॉप- 12 में जगह नहीं बना सकीं। 4 राउंड के बाद टॉप-5 में थाइलैंड की प्रवीनार सिंह, फिलीपींस की आतिसा मनालो, वेनेजुएला की स्टेफनी अबसाली, मेक्सिको की फातिमा बोश फर्नांडेस और आइवरी कोस्ट की ओलिविया यासे ने जगह बनाई थी। इसके बाद मेक्सिको की फातिमा बोश को विनर घोषित किया गया। मिस यूनिवर्स 2025 में थाइलैंड की कंटेस्टेंट प्रवीनार सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वेनेजुएला की स्टेफनी अबसाली तीसरे नंबर पर रहीं। फिलीपींस की आतिसा मनालो चौथे और आइवरी कोस्ट की ओलिविया यासे पांचवें स्थान पर रहीं। एक इंटरव्यू में फातिमा बोश फर्नांडीज ने बताया कि उनका बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा।

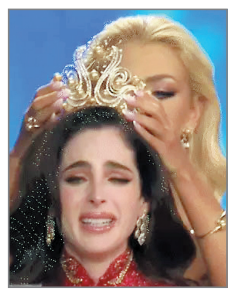

प्रदेश की समृद्धि के लिए गांवों को जोड़ा जा रहा है विकास और स्वावलंबन की धारा से : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कागपुर में 39.80 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि-पूजन

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के गरीब, किसान, बहनों और युवाओं के कल्याण के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश की समृद्धि के लिए गांवों को विकास और स्वावलंबन की धारा से जोड़ा जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए गोपालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं। किसानों को भावांतर योजना की राशि दी जा रही है। प्रदेश के हर गांव और हर खेत को पानी मिले, यही हमारी सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जल स्त्रोतों का संरक्षण किया गया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श वृंदावन ग्राम विकसित करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। शुक्रवार को शमशाबाद का कागपुर जनसहयोग से श्रेष्ठतम ग्राम बनने का एक आदर्श उदाहरण है। सर्व सुविधा युक्त इस गांव को नए हाट बाजार की सौगात मिली है, जिसमें 128 दुकानें तैयार की गई हैं। यह बाजार आसपास की बड़ी आबादी के लिए हाट बाजार का प्रमुख केंद्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कागपुर में म.प्र. टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से वॉटर पार्क बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव विदिशा के कागपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर जल संरक्षण और जल स्त्रोतों के विकास का कार्य किया गया है। केन-बेतवा परियोजना से विदिशा जिले में सिंचाई के लिए कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में वर्ष 2026 तक श्मशान घाट और सड़कों सहित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएगी। विकास का कोई भी क्षेत्र अधूरा नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सांदीपनि विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना से गोपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा और अन्य सभी बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। रोजगार के साधन बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदर्श ग्राम पंचायत कागपुर में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसमें श्री सौदान सिंह का विशेष योगदान जिन्होंने हाट बाजार के लिए भूमि दान की थी।

किसानों को भावान्तर योजना से मिल रहा फसलों का उचित मूल्य- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कागपुर में आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 5.75 करोड़ लागत के हाट बाजार का लोकार्पण किया। उन्होंने 2 हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप दुकानों की चाबी सौंपी। साथ ही विदिशा जिले के लिए 34 करोड़ लागत से 135 नवीन स्वीकृत सामुदायिक भवनों का भूमि-पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को भावान्तर योजना के माध्यम से फसलों का उचित दाम दे रही है।

भारत के लिए दुखद खबर, दुबई एयर शो में तेजस क्रैश

दुर्घटना में पायलट की हो गई मौत; वायुसेना ने की पुष्टि

नई दिल्ली (एजेंसी)। एक दुखद खबर आ रही है। दुबई एयर शो में भारत का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार, इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। दुर्घटना का यह दृश्य बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। जांच टीमें घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई हैं। हादसे में पायलट को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। वायुसेना ने इस दुखद हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है और कहा है कि इस कठिन समय में वह शोकग्रस्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन के आदेश दिए हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार, दुबई एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का एलसीए तेजस विमान क्रैश हो गया है। सीनियर जर्नलिस्ट आदित्य कौन ने इस घटना का वीडियो शेयर किया जो काफी दुखद है। भारतीय वायुसेना ने भी पुष्टि की है कि दुबई एयर शो 2025 में तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। घटना से जुड़ी अन्य जानकारियां अभी एकत्रित की जा रही हैं। दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान एरोबैटिक डिस्प्ले के दौरान अचानक नीचे की ओर गोता लगाते हुए क्रैश हो गया।

● दुबई में जुटी थीं दुनियाभर की एयरोस्पेस कंपनियां- दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों का प्रदर्शन किया जाता है। यहां दुनिया की बड़ी एयरोस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयर फोर्सेज और टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, हथियार सिस्टम और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी दिखाती हैं। पांच दिन के एयरशो का शुक्रवार को आखिरी दिन था। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 हुई थी। इसे दुबई के अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हर दो साल पर आयोजित किया जाता है। यह लगातार तीसरी बार है जब तेजस इसमें शामिल हुआ था।

ब्राजील में सीओपी30 क्लाइमेट समिट के हॉल में भीषण आग

● 13 घायल,भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहीं मौजूद थे

ब्रासीलिया (एजेंसी)। ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहे सीओपी 30 क्लाइमेट समिट के मेन वेन्यू पर गुरुवार को आग लग गई। इसमें 13 लोग घायल हो गए। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी आग लगने के समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वहीं मौजूद थे। हालांकि, वे और अन्य अधिकारी सुरक्षित रूप से कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, यह आग स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे एक कन्वेंशन हॉल के अंदर एक पवेलियन में लगी थी।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c | न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 22 नवंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

पाकिस्तान के फैसलाबाद में हो गया भीषण धमाका

● आसपास के मकानों की छतें तक उड़ीं,15 की मौत

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शुक्रवार को एक फैक्ट्री में हुए धमाके में कम से कम 15 मजदूरों की मौत हो गई है। ये धमाका फैसलाबाद के मलिकपुर इलाके की फैक्ट्रियों में हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि उनको शुक्रवार सुबह फैक्ट्री में धमाके की सूचना मिली। धमाका इतना जोरदार था ना कि इससे ना सिर्फ फैक्ट्री का शेड और बिल्डिंग बल्कि आसपास के कई मकान तक गिर गए। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, रेस्क्यू सर्विस ने शुरुआती जांच के बाद धमाके की वजह गैस लीक बताई है। फैसलाबाद कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि यहां आसपास चार फैक्ट्री हैं। फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं था। गैस लीकेज की वजह से एक फैक्ट्री में आग लगी और दूसरी फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई। फैसलाबाद कमिश्नर ने कहा है कि इलाके के सात घर भी इस हमले से प्रभावित हुए। धमाके की वजह से कई घरों की छत गिर गई।

उत्तराखंड के गांव को उपचुनाव में भी नहीं मिलेगा प्रधान

राजी महिला के लिए था आरक्षण, पूरे गांव में एक भी नहीं मिली 8वीं पास

पिथौरागढ़ (एजेंसी)। उत्तराखंड में गुरुवार को 321 पदों के लिए त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, परिणाम शनिवार को आने हैं। लेकिन पिथौरागढ़ जिले की खेतार कन्याल ग्राम पंचायत में रिजल्ट के बाद भी कोई प्रधान नहीं बनेगा। दरअसल, इस ग्राम पंचायत में प्रधान की सीट अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित थी और शर्त थी कि महिला कम से कम आठवीं पास हो। लेकिन, पूरे गांव में कोई भी

वनराजी (राजी जनजाति) महिला 8वीं पास नहीं मिली जिससे उपचुनाव में भी नामांकन नहीं हो सका। इस संबंध में पिथौरागढ़ के पंचस्थानिक अधिकारी भुवन उप्रेती कहते हैं कि उच्च अधिकारियों को इस समस्या के संबंध में बता दिया गया है जो भी आगे से निर्देश मिलेंगे उसी के आधार पर आगे का फैसला होगा। खेतार कन्याल पिथौरागढ़ के डीडीहाट ब्लॉक में आता है। 2011 में आखिरी बार हुई जनगणना की मानें तो इसकी कुल आबादी 920 है। वहीं गांव में 162 वनराजी हैं, लेकिन इस जनजाति की कोई भी महिला यहां पर 8वीं पास नहीं है, शिक्षा की दयनीय स्थिति सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है।

नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर पर दिग्विजय ने उठाए सवाल

हत्या के आरोप वाला वीडियो शेयर किया, भाजपा बोली- शहीद इंस्पेक्टर के लिए एक शब्द नहीं कहा

भोपाल (नप्र)। छत्तीसगढ़ के इनामी नक्सली माड़वी हिड़मा के एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। इससे वे विवाद के केंद्र में आ गए।

दिग्विजय ने आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सोनी एनकाउंटर को फर्जी बता रही हैं। इसमें कहा है कि 'यह एनकाउंटर नहीं, हत्या थी।' सोढ़ी के वीडियो को शेयर करने पर भाजपा ने हमला तेज कर दिया। सांसद आलोक शर्मा ने कहा- राष्ट्र के लिए जो सैनिक शहीद होते हैं, उनके लिए दिग्विजय कुछ नहीं कहते। उनका बयान हमेशा आतंकवादियों के पक्ष में ही क्यों होता है? जनता सब जानती है, इसलिए उनकी पूरी पार्टी को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ रहा है।

वहीं, कालापीपल से भाजपा विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने दिग्विजय पर आरोप लगाया कि एमपी के नरसिंहपुर के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। दिग्विजय सिंह ने उनके लिए संवेदना भरा एक शब्द नहीं कहा, लेकिन हिड़मा जैसे खूंखार नक्सली के लिए सवाल उठा रहे हैं। कम से कम संवेदना के तौर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देते। आंध्र प्रदेश के अल्लुरी सिताराम राजू जिले में 18 नवंबर को हिड़मा और उसकी पत्नी राजे समेत 6 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। सोढ़ी अंतिम संस्कार में शामिल हुई थीं। दिग्विजय सिंह ने खुद को नक्सली हिंसा का विरोधी बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- समझौते कर आत्मसमर्पण कराना चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूं। विषय कुछ और है। उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मेनस्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार छिने हैं।

बेंगलुरु के ट्रैफिक में फंसे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला

● कहा-अंतरिक्ष में यात्रा करना शहर के खराब ट्रैफिक को पार करने से कहीं ज्यादा आसान

बेंगलुरु (एजेंसी)। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने बेंगलुरु के खराब ट्रैफिक पर मजाकिया लहजे में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में यात्रा करना शहर के खराब ट्रैफिक को पार करने से कहीं ज्यादा आसान है। शुभांशु गुरुवार को कर्नाटक सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स,आईटी और बीटी विभाग ने फ्यूचराइज थीम पर बेंगलुरु टेक समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उन्होंने मराठाहल्ली से बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर तक लगभग 34 किमी का सफर तय किया। इसे तय करने में आमतौर पर एक घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। उन्हें कितना वक्त लगा। यह पता नहीं

चल पाया। उन्होंने कहा, मैं बेंगलुरु के दूसरे छोर पर स्थित मराठाहल्ली से यहां पहुंचा हूं। मेरे इस प्रेजेंटेशन में जितना समय लगेगा, उससे तीन गुना समय मैंने सिर्फ सड़क पर बिताया है। उम्मीद है कि आप मेरे कमिटमेंट को समझेंगे। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने शुभांशु के टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि सरकार शहर में यात्रा समय कम करने और ट्रैफिक प्रबंधन सुधारने की दिशा में काम कर रही है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी दिक्कतें आगे न हों। जून 2025 में जारी ट्रैफिक पुलिस के हीटमैप के मुताबिक बेंगलुरु में हर दिन करीब 190 किमी तक लंबा जाम लगता है। 2024 के मुकाबले इस साल लोगों का वन-वे सफर 16 फीसदी बढ़ गया है, यानी करीब 63 मिनट लग जाते हैं।

चीन को अब समुद्र में टक्कर देगा भारत

● सरकार से 'स्मार्ट जंगी जहाज' बनाने की मंजूरी मांगने वाली है नौसेना

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को देखते हुए इंडियन नेवी भी पूरी तरह अलर्ट है। भारतीय नौसेना सरकार से कम से कम पांच अगली पीढ़ी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज बनाने की मंजूरी मांगने की तैयारी कर रही है। ये जहाज स्मार्ट वॉरशिप होंगे, जिनमें ज्यादा मारक क्षमता और कई नई तकनीकें होंगी। इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ वाइस

एडमिरल संजय वात्स्यायन ने बताया, हमने एक बेहतरीन डिजाइन तैयार कर लिया है और उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में हमें सरकार से स्वीकृति मिल जाएगी। अगले दो सालों के अंदर हम इनके प्रोडेक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे। ये नए जहाज अभी नौसेना के पास मौजूद हैं।

मुख्यमंत्री ने किया तीन दिवसीय फेड एक्सपो-2025 का शुभारंभ

म.प्र. उद्योगों के लिए पसंदीदा राज्य, एक्सपो उद्योगों को दुनिया से जोड़ने में सहायक: मुख्यमंत्री

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ पसंदीदा राज्य बन रहा है। फेड एक्सपो जैसे आयोजन स्थानीय उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच से जोड़ने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे एक्स्पो उद्योग-धंधों, नवाचार और एमएसएमई सेक्टर के विकास के लिए एक बड़ा मंच साबित होते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को गोविन्दपुरा में आयोजित फेड एक्सपो-2025 समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने, एमएसएमई सेक्टर को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गोविन्दपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के एग्जिबिशन हॉल में फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित तीन दिवसीय फेड एक्सपो-2025 का दीप प्रज्ज्वलन कर विधिवत् शुभारंभ किया। यह एक्सपो 23 नवम्बर तक चलेगा। एक्सपो में मध्यप्रदेश सहित देश-विदेश से आए उद्योग एवं एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्यमियों,

निवेशकों और संस्थानों ने व्यापक रूप से भागीदारी की। एक्सपो में रूस, ओमान और ताईवान देशों से भी उद्यमी आए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इपिक प्रोजेक्ट का विमोचन किया। इससे स्व-सहायता समूह, स्कूल, कॉलेज, ग्राम पंचायतें, शासकीय कार्यालय सभी एक प्लेटफार्म से जुड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रदेश में 1000 इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। जहां हर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इपिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों और निवेशकों को 5000 एकड़ जमीन दी गई है। यह एक प्रकार से पांच हजार उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश आने का निमंत्रण है।

हैदराबाद में 22 नवंबर को होगा इन्वेस्टर्स के लिए रोड-शो

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 22 नवंबर को हम हैदराबाद में वहां के इन्वेस्टर्स से संवाद करने के लिए रोड-शो करने जा रहे हैं। यह सरकार के लिए उद्योग-रोजगार वर्ष है। जीआईएस और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से मिले सभी निवेश प्रस्तावों में से अब तक हम 8 लाख करोड़ रुपये के अधिक निवेश प्रस्तावों पर ठोस कार्यवाई कर चुके हैं। इनमें से 6 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली औद्योगिक इकाइयों का सामूहिक भूमिपूजन करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री को आमंत्रण दिया है। हम उनकी उपस्थिति में यह ऐतिहासिक भूमिपूजन संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि बीते 4 दशकों में व्यापार-व्यवसाय की संभावनाओं को देखा जाए, तो इसमें मध्यप्रदेश फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भूमिका बड़ी अहम रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नया मध्यप्रदेश गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी कोशिश है कि गरीबों की गरीबी दूर हो और युवाओं को रोजगार मिले, प्रदेश में सुख-समृद्धि आए और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने।

फरीदाबाद के घर में मिली 'बम' बनाने वाली मशीन

डॉ. मुज्जमिल से है कनेक्शन,दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा

फरीदाबाद (एजेंसी)। दिल्ली में लाल किले के नजदीक कार में बम ब्लास्ट की आतंकी घटना से पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉ. मुजम्मिल शकील को अरेस्ट किया था। इसके बाद दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देते हुए डॉ. उमर उन बनी ने सुसाइड बॉम्बर के तौर कार में विस्फोट किया था। इसमें 13 लोग मारे गए थे। जांच एजेंसियों ने अब डॉ. मुजम्मिल शकील जुड़े एक ऐसा खुलासा किया है। जिससे आप भी हिल जाएंगे। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े इस डॉक्टर ने एक आटा चक्की को आतंक का सामान पीसने यानी बम बनाने की मशीन में बदल दिया था। फरीदाबाद के एक घर में इसकी बरामदगी सामने आई है। तस्वीरों से पता चला है कि मुजम्मिल शकील ने अपना विस्फोटक सेटअप बना रखा था। गौरतलब हो कि मुजम्मिल शकील के साथी डॉ. उमर ने ही दिल्ली में कार विस्फोट को अंजाम दिया था। जिसकी जांच एनआईए की अगुवाई में चल रही है।

● **दो साल की प्लानिंग के मिले सबूत-** जांचकर्ताओं का दावा है कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह पूरा मॉड्यूल दो साल से चल रहा था। बेहद सावधानी के साथ प्लानिंग की जा रही थी। गौरतलब हो कि फरीदाबाद से हथियार और 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिलने पर पूरा देश हिल गया था। अब सामने आया है कि फरीदाबाद के धौज गांव के एक शांत घर में दिल्ली कार ब्लास्ट में सह-आरोपी डॉ. मुजम्मिल ने आटा चक्की को केमिकल वर्कशॉप में बदल दिया था। हरियाणा के फरीदाबाद में एक टैक्सी ड्राइवर के घर से मिली चक्की और बिजली की मशीनरी की तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है कि कैसे रोजाना इस्तेमाल होने वाला अनाज पीसने वाली मशीन को केमिकल को पाउडर बनाने का टूल बन दिया था। आटा चक्की असल में एक ग्राइंडर होती है। इसमें ठोस चीजों को बारीक पाउडर में बदलने के लिए भारी रोलर या ब्लेड होते हैं। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से 2900 किलोग्राम विस्फोटक की बरामदगी की थी। जहां से यह विस्फोटक मिला था।

एसआईआर को एक बार फिर मिली 'सुप्रीम' चुनौती

उच्च अदालत ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरल, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों के एसआईआर के निर्वाचन आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे जुड़ी याचिकाओं के एक बैच पर एससी ने सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई। जज सूर्यकांत, जज एसवीएन भट्टी और जज जॉयमाल्या बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न आधार पर एसआईआर की कवायद को चुनौती देने वाली विभिन्न नेताओं की सभी नई याचिकाओं पर आज सुनवाई की। केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से

सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं। इसलिए इस मामले में तत्काल विचार की आवश्यकता है। पीठ ने निर्देश दिया कि केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 26 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। दूसरे राज्यों में इस कवायद को चुनौती देने वाली बाकी याचिकाओं पर दिसंबर में सुनवाई होगी।

जज बोले-राहुल गांधी 18 दिसंबर को हाजिर हों

● 7 महीने पहले कहा था-भगवान राम काल्पनिक हैं

उत्तरप्रदेश की वाराणसी कोर्ट में हो रही है सुनवाई

वाराणसी (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी या उनके वकील शुक्रवार को भी वाराणसी कोर्ट नहीं पहुंचे। इस वजह से उनके मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुर्वेद विक्रम सिंह ने कहा कि अगली सुनवाई (18 दिसंबर) पर राहुल गांधी या उनके वकील कोर्ट आएं। जिससे सुनवाई हो सके। राहुल गांधी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान राम को काल्पनिक कहने का आरोप है। इस मामले में वकील हरिशंकर पांडेय ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने 12 मई को याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी 21 अप्रैल को अमेरिका के बोस्टन गए थे। यहां पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था। यहां राहुल ने भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को 'पौराणिक' बताया था।

चीन-जापान तनाव से इंडियन सी-फूड की डिमांड बढ़ी

अमेरिकी टैरिफ झेल रहे एक्सपोर्टर्स के शेयर 10 फीसदी तक चढ़े

नई दिल्ली (एजेंसी)। चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर बढ़ते तनाव का सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। चीन ने बुधवार को जापान से आने वाले सभी सीफूड (जैसे- मछली, झींगा) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भारतीय सीफूड निर्यातकों के शेयरों में तेज उछाल देखने को मिला। चीन के इस फैसले से उसके बाजार में सीफूड की कमी का खतरा पैदा हो गया है। इसे पूरा करने के लिए वह भारत जैसे देशों की तरफ तेजी से रुख कर रहा है। इसके चलते भारतीय सीफूड कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है।

तेलंगाना की अवंती फीड्स के शेयर करीब 10 फीसदी तक चढ़ गए। यह कंपनी के शेयर में पिछले दो महीनों में सबसे बड़ी बढ़त है। वहीं एक और सीफूड कंपनी कोस्टल कॉरपोरेशन के शेयर भी 5 फीसदी बढ़े। कंपनी

ने अप्रैल में कहा था कि वह चीन को निर्यात बढ़ाएगी। चीन और जापान के बीच विवाद की वजह जापानी पीएम साने ताकाइची का एक बयान है। दरअसल ताकाइची ने 7 नंवबर को कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा। चीन ने इस बयान को बेहद गैर-जिम्मेदार और उकसाने वाला बताया। इसके अगले ही दिन विवाद और बढ़ गया जब जापान में चीन के काउंसल जनरल शुए जियान ने एक्स पर लिखा कि वह इस मामले में दखल देने वाले की गर्दन काट देंगे। इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजदूतों को तलब किया। चीन ने अपने नागरिकों को जापान न जाने के लिए आगाह किया है और चेतावनी दी है कि वहां जाने पर उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। भारत के लिए चीन के बाजार का मौका ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारतीय सीफूड पर 50 फीसदी तक का टैक्स लगा रखा है।

'सुगम परिवहन सेवा' इंदौर से शुरू होगी

20 साल बाद फिर शुरू होगी सरकार नियंत्रित परिवहन सेवा वाली बसें

सरकारी नियंत्रण में 10 हजार बसें चलेंगी

इंदौर। प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी नियंत्रण वाली यात्री बसें अप्रैल, 2027 तक संचालन में आ जाएंगी। सुगम परिवहन सेवा की इस योजना के अंतर्गत कुल 10,879 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें निजी ऑपरेटरों की होंगी, लेकिन इनके संचालन, प्रबंधन और किराया संरचना पर पूरा नियंत्रण शासन के पास रहेगा।

साल 2005 में 700 करोड़ रुपये से अधिक घाटे के कारण मप्र राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से बस संचालन पूरी तरह निजी क्षेत्र पर निर्भर था, जिससे मनमाना किराया, असुरक्षित यात्रा, वाहनों की खराब फिटनेस और क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जाने जैसी समस्याएं लगातार सामने आ रही थीं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पदभार ग्रहण करने के बाद दोबारा सरकारी सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह योजना लागू की जा रही है। सुगम परिवहन सेवा योजना की शुरुआत अप्रैल, 2026 से इंदौर के आठ अंतर शहरी और 24 उपनगरीय मार्गों पर की जाएगी। संचालन कार्य में देरी न हो, इसलिए हर चरण और गतिविधि की स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी गई है। बसों का किराया शुरुआती एक किलोमीटर के लिए सात रुपये तथा उसके बाद प्रति किमी 1.25 रुपये निर्धारित है। इसी दर से 50 किमी का किराया 70 रुपये बनता है, जबकि वर्तमान में निजी बस संचालक 50 प्रतिशत तक अधिक किराया वसूल रहे हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में बस सेवा को चरणबद्ध ढंग से पूरे प्रदेश में लागू करने की रूपरेखा तय की गई। तय कार्यक्रम के अनुसार सेवा शुरू होने के एक वर्ष के भीतर सभी जिलों में सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध होगी। फिलहाल इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर के लिए यात्रियों की संख्या एवं मार्ग सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है।

परिवहन विभाग ने इंदौर संभाग के जिलों के मार्ग 15 दिसंबर, 2025 तक और उज्जैन क्षेत्र के मार्ग 26 नवंबर से पहले निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है। बसों के व्यवस्थापन के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें व्हीकल लोकेशन, ट्रैकिंग, किराया संग्रहण और अलर्ट जैसे 18 मॉड्यूल शामिल हैं। हालांकि आईटीएमएस सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्माण मई, 2026 तक संभव होगा।

किराया और संचालन समय

10 किमी-19 रुपए, 20 किमी-32 रुपए, 30 किमी 45 रुपए, 40 किमी-57 रुपए और 50 किमी-70 रुपए होगी। पहले चरण में इंदौर शहर से 50 किमी दायरे के शहरी व अंतर शहरी 32 रूट पर 310 बसें अप्रैल, 2026 तक चलना शुरू हो जाएंगी। दूसरे चरण में इंदौर संभाग के सभी जिलों के 771 रूट पर 1706 बसें जून, 2026 तक चलने लगेंगी। तीसरे चरण में भोपाल व उज्जैन शहर से 50 किमी दायरे वाले रूट बसें चलना शुरू होंगी। भोपाल के 50 और उज्जैन के 23 रूट पर बसों का संचालन होगा। जुलाई 2026 तक भोपाल के 152 और उज्जैन के 127 रूट तय किए गए हैं। बसों के संचालन के चौथे चरण में उज्जैन संभाग के सभी जिलों के 386 रूट के लिए 1318 बसें नवंबर 2026 तक चलना शुरू हो जाएंगी। पांचवें चरण में सागर और जबलपुर संभाग के 1228 रूट पर 2635 बसें दिसंबर, 2026 तक चलेंगी। छठे चरण में भोपाल व नर्मदापुरम संभाग में 1843 बसों का संचालन अप्रैल 2027 तक होगा। सातवें चरण रीवा एवं शहडोल संभाग में 1470 बसें अप्रैल 2027 तक चलने लगेंगी। इस योजना का आठवां चरण ग्वालियर एवं चंबल संभाग के लिए होगा, जहां 1318 बसें निर्धारित रूट पर संचालित की जाएंगी।

नेशनल शूटर से छेड़छाड़ मामले में बस जब्त, ड्राइवर, हेल्पर गिरफ्तार

पुलिस ने बस संचालक-मैनेजर की भूमिका की जांच भी शुरू की

इंदौर। नेशनल स्तर की शूटिंग खिलाड़ी के साथ बस में हुई छेड़छाड़ के मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वर्मा ट्रेवल्स के दो ड्राइवर और एक हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इंदौर-पुणे रूट पर चलने वाली लग्जरी बस (एमपी 09 एजी 0336) को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस अब बस संचालक और मैनेजर की भूमिका की भी जांच करेगी।

डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के अनुसार पीड़िता पुणे की रहने वाली है और पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने 16 नवंबर को भोपाल आई थी। नेशनल गेम्स में भाग लेने के बाद वह वर्मा ट्रेवल्स की बस से वापस पुणे लौट रही थी। इसी दौरान हेल्पर परमेंद्र गौतम ने सीट संबंधी बहाने से पर्दा हटाया और उसके साथ छेड़छाड़ की। आरोपी शराब के नशे में था और यात्रियों द्वारा डांटने पर वहां से हट गया।

बस राजेंद्र नगर थाने के सामने से गुजर रही थी, तभी पुलिस चेकिंग देखकर तीनों आरोपी घबरा गए और बस को पास के मंदिर के समीप खड़ी कर फरार हो गए। पुलिस द्वारा दबाव बनाने पर बस मैनेजर विनोद वर्मा ने तीनों को थाने भेजकर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाई। पीड़िता पहले लिखित शिकायत देकर पुणे चली गई थी। गुरुवार को वह वकीलों के साथ वापस आई और विस्तार से बयान दर्ज करवाए। टीआई नीरज बिरथरे ने बताया कि आरोपी दीपक मालवीय,परमेंद्र गौतम और अरविंद वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पीड़िता ने बताया कि उसने आरोपियों की फोटो लेकर बस मैनेजर को शिकायत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद वे अश्लील हरकतें करते रहे। पुलिस का कहना है कि बस संचालक की भूमिका और आरोपियों के नशे में होने के कारणों की भी जांच की जा रही है।

ब्रिलिएंट स्कूल में धूमधाम से मना वार्षिकोत्सव

इंदौर। कनाडिया रोड स्थित मानवता नगर के ब्रिलिएंट स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम छात्रों के लिए एक अनोखा अनुभव रहा, जिसमें उन्होंने सांस्कृतिक, देश भक्ति और धार्मिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रभावशाली अंदाज़ में प्रस्तुत किया। भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक वेशभूषा में सजे छात्रों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल की डायरेक्टर के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाना है। एनिमल थीम आधारित गतिविधियों में बच्चों ने खूब आनंद लिया और साथियों के संग यादगार पल साझा किए। संस्थान में पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार, खेलकूद और सह-पाठ्य गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और शिक्षक उपस्थित रहे और सभी ने प्रस्तुतियों की सराहना की।

ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में दोषमुक्त

इंदौर। ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा डालने के 2007 के चर्चित मामले में अभियोजन पक्ष कोर्ट में ड्यूटी संबंधी प्रमाण ही पेश नहीं कर पाया, जिसके चलते आरोपी विक्रम यादव और अब्दुल रज्जाक को दोषमुक्त कर दिया गया। मामला 29 अक्टूबर 2007 को पलासिया चौराहे का है, जहां कथित रूप से ट्रैफिक पुलिसकर्मी भगवान गुर्जर से वाहन हटाने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप था कि आरोपियों ने पुलिसकर्मी से मारपीट कर वर्दी और नेमप्लेट फाड़ दी थी। विचारण न्यायालय ने पहले इन्हें आईपीसी धारा 353 व 332 के तहत तीन माह साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई थी। परंतु अपील में अभियोजन कहानी स्वतंत्र साक्षियों के अभाव और विरोधाभासों के कारण टिक नहीं सकी। अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. शुभ्रा सिंह की कोर्ट ने कहा कि घटना के समय पुलिसकर्मी की ड्यूटी का कोई दस्तावेज, रोजनामचा या वरिष्ठ अधिकारी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी आधार पर निर्णय अपास्त कर दोनों को दोषमुक्त किया गया।

बीएलओ नीरज चौधरी जिले में प्रथम

इंदौर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएआर) का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसी क्रम में सांवेर विधानसभा के सुराखेड़ी में पदस्थ बीएलओ नीरज चौधरी ने शत-प्रतिशत पुनरीक्षण कार्य पूरा कर जिले ही नहीं, बल्कि पूरे संभाग में पहला स्थान प्राप्त किया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शिवम वर्मा ने उनकी कर्तव्यनिष्ठा की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की तत्परता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाती है। एसडीएम घनश्याम धनगर ने भी चौधरी को सम्मानित किया और बताया कि भाग संख्या 35 का SIR-2025 कार्य समय पर और पूर्णतः डिजिटलाइज्ड रूप में संपन्न हुआ है।

भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी पर केस

देवास। अंतरराष्ट्रीय जुजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम की आत्महत्या मामले में पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कोच विजेंद्र खरसोदिया और मध्यप्रदेश जुझित्सु संघ के उपाध्यक्ष एवं भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री प्रीतम सिंह पर आत्महत्या के लिए उकसाने और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं कोच विजेंद्र फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। गत माह रोहिणी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला था, जिससे जांच शुरुआती दौर में उलझी रही। बाद में मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल और चैट विश्लेषण में सामने आया कि रोहिणी की नियमित बातचीत कोच विजेंद्र और प्रीतम सिंह से होती थी। परिवार ने भी प्रारंभ से दोनों पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि रोहिणी लंबे समय से मानसिक दबाव में थी। रोहिणी की बहन रोशनी कलम ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।

दुकानों के सामने ई-रिक्शा खड़े हो रहे, रोजाना बढ़ रहे विवाद

ट्रैफिक पुलिस की चुप्पी की वजह से कोई कार्रवाई नहीं

इंदौर। शहर में बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। खासकर प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक इलाकों में दुकानों के सामने ई-रिक्शा खड़े होने से न केवल जाम की स्थिति बनती है, बल्कि रोजाना विवाद की नौबत भी आती है। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। मालवा मिल, परदेशीपुरा, तीन पुलिया जैसे इलाकों में दिनभर बड़ी संख्या में ई-रिक्शा सवारी के इंतजार में दुकानों के सामने खड़े रहते हैं। इससे ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में मुश्किल होती है, वहीं व्यापारी भी परेशान हैं। कई बार ई-रिक्शा चालकों और दुकानदारों के बीच झगड़े की नौबत तक आ जाती है। बावजूद इसके, ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंचकर केवल समझाइश देकर लौट जाती है, जिससे समस्या जस की तस बनी हुई है।

भेदभावपूर्ण कार्रवाई से रोष- क्षेत्रीय दुकानदारों को कहना है कि ट्रैफिक पुलिस शहर को यातायात में नंबर वन बनाने का ढिंढोरा पीटती है। लगातार बेहतर ट्रैफिक को लेकर काम किया जाता है। लेकिन, पुलिस भेदभावपूर्ण कार्रवाई करती है, जिसका खामियाजा आमजन के साथ दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है।

रिक्शा वाले दुकानों के मुहाने पर इस तरह खड़े हो जाते हैं कि दुकानदार को दुकान के गेट तक पहुंचने में परेशानी आती है। ऐसे में वह रिक्शा हटाने को कहता है तो चालक गाली-गलौज करते हैं।

परदेशीपुरा, तीन पुलिया, पाटनीपुरा के दुकानदारों ने ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई के लिए यातायात पश्चिम जोन के एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) मनोज खत्री, डीसीपी आनंद कलादगी को फोटो भेजकर शिकायत की, लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई करने में रुचि नहीं दिखाई। पुलिस की अनदेखी और रिक्शा चालकों की पीड़ा से त्रस्त दुकानदारों ने कार्रवाई के लिए सीएम हेल्प लाइन में शिकायत की है। शिकायत का निराकरण नहीं हुआ तो यातायात पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। पुलिस उपायुक्त (यातायात) आनंद कलादगी ने कहा कि परदेशीपुरा में ई रिक्शा खड़े होने की शिकायत मिली थी। दुकानदारों को ट्रैफिक हेल्पलाइन में शिकायत करना चाहिए। काम की व्यस्तता के कारण ई रिक्शा पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात (पश्चिम) मनोज खत्री ने कहा कि मुझे शिकायत मिली थी, लेकिन जरूरी काम में बाहर आ गया हूं। कुछ जवानों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन वे मौके पर नहीं पहुंच सके।

शहर में बिना हेलमेट लाखों घूम रहे, कार्रवाई केवल कुछ हजार पर ही

चुनिंदा चौराहों पर ही ट्रैफिक पुलिस का अभियान चल रहा

इंदौर। सड़क हादसे रोकने पुलिस लगातार हेलमेट पहनने पर जोर दे रही है। इसे लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ उनका वितरण भी किया जा रहा है। एक सप्ताह पहले हेलमेट को लेकर वृहद पैमाने पर अभियान भी शुरू किया है। चुनिंदा चौराहों पर अभियान में केवल एक से डेढ़ हजार चालकों के ही चालान बनाए जा रहे हैं, जबकि रोजाना लाखों वाहन चालक बिना हेलमेट के आवाजाही कर रहे हैं।

कई वाहन चालक तो चालानी कार्रवाई में लगे पुलिस जवानों के साथ बेखौफ निकल जाते हैं। ट्रैफिक में शहर को नंबर वन बनाने के प्रयासों को खुद यातायात विभाग पलीता लगा रहा है। विभाग की कथनी और करनी में अंतर है। पूरे शहर में यातायात का कबाड़ा निकल रहा है और अधिकारी चंद लोगों पर कार्रवाई कर बेहतर कर्तव्य निर्वहन का ढोल पीट रहे हैं। अधिकारियों के समक्ष नियमों का मखौल उड़ता है और वे काम को बोझ होने, कर्मचारियों की कमी को रोना रोते हैं। कुछ चौराहों पर हालत इतने बदतर हैं कि रिक्शा वालों के कारण आमजन को निकल पाना मुश्किल हो जाता है।

जवान नहीं लगाते हेलमेट

नियमों का कड़ाई से पालन कराने की सीख देने वाले यातायात विभाग के जवान भी हेलमेट नहीं लगाते। पांच दिन पहले जब पुलिस कमिश्नर ने बगैर हेलमेट आए जवानों के चालान बनाए थे, तभी उन्होंने हेलमेट पहना था। वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे जवानों की जानकारी है, लेकिन वे जवानों पर कार्रवाई नहीं करते। पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक आनंद कलादगी ने कहा कि रोजाना एक हजार के आसपास बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों के चालान बनाए जा रहे हैं। बल की कमी के कारण अधिक चालान बनाना संभव नहीं है। कई चौराहों पर चालान नहीं बन रहे हैं।

छह लाख की एमडी ड्रग के साथ तस्कर गिरफ्तार, बड़ी सफलता

आरोपी पेंटर का काम करता और पांचवीं तक शिक्षित

इंदौर। अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में क्राइम ब्रांच को महत्वपूर्ण सफलता मिली। टीम ने लक्ष्मीबाई नगर स्थित माल गोदाम कार्यालय के पास दबिश देकर राजस्थान के झालावाड़ निवासी कुलदीप मेघवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 60.08 ग्राम एमडी जब्त की गई,जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 लाख रुपये आंकी गई है। क्राइम ब्रांच टीम क्षेत्र में लगातार संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश कर रही थी,इसी दौरान एक युवक पुलिस को देखते ही घबराकर भागने लगा। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम कुलदीप मेघवाल बताया। उसकी तलाशी लेने पर अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद हुई, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में कुलदीप ने स्वीकार किया कि वह सस्ते दामों पर एमडी खरीदकर इंदौर में नशे के आदी युवाओं को अधिक कीमत पर बेचता था। आरोपी पेंटर का काम करता है और केवल पांचवीं तक शिक्षित है, लेकिन आसान पैसे के लालच में नशे की तस्करी में शामिल हो गया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

महापौर का निरीक्षण, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश

साफ-सफाई समेत कई व्यवस्थाओं से नाराजगी जताई

इंदौर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज प्रातः जोन क्रमांक 20 के तहत वार्ड क्रमांक 8 के छिपा बाखल,अहिल्या पलटन,चौथी पलटन, तंबोली बाखल, मल्हारगंज सहित आसपास के क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। महापौर ने गोराकुंड से सुभाष मार्ग तक प्रस्तावित ड्रेनेज लाइन कार्य की स्थिति जानी और रहवासियों की समस्याएं सुनीं। यातायात अवरोध और देरी को गंभीर मानते हुए उन्होंने विभाग को कार्य तुरंत प्रारंभ करने के निर्देश दिए। छीपा बाखल क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ न करने पर महापौर ने तीखी नाराजगी जताई। अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी करने की जानकारी मिलने पर उन्होंने कहा कि

आपका काम सिर्फ नोटिस देना नहीं है,काम करवाना है। ठेकेदार काम न करे तो उसे ब्लैकलिस्ट कर टेंडर निरस्त करें। चौथी पलटन में बोरिंग के बाद भी जल प्रदाय लाइन न डाले जाने पर महापौर ने कड़ी फटकार लगाते हुए दिन में ही कनेक्शन पूरा करने के निर्देश दिए।

तंबोली बाखल क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन गलत तरीके से डालने और सफाई के बाद भी गाद न उठाए जाने पर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि क्या एक साल बाद गली से गाद उठाएंगे! इसके साथ ही उन्होंने कचरा फैलाने वालों पर कड़ी चालानी कार्रवाई और बाधक वाहनों को तुरंत जब्त करने के निर्देश दिए।

हथियार तस्करी का खुलासा, 12 पिस्टल के साथ बुलंदशहर का युवक गिरफ्तार

पुलिस ने नेटवर्क खंगालना शुरू किया, बड़ी साजिश की आशंका

इंदौर। छत्रीपुरा थाना पुलिस ने हथियारों की तस्करी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक संदिग्ध बैग लेकर इलाके में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। उसकी पहचान दीपक शर्मा, निवासी बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई है। जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से 12 देशी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद

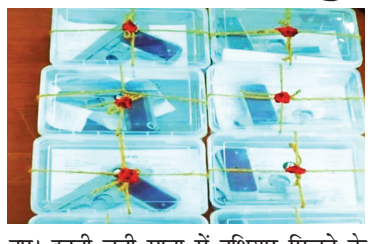

हुए। इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचना दी गई और आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि वह लंबे समय से अवैध हथियार सप्लाई के काम से जुड़ा हो सकता है, हालांकि वह यह स्पष्ट नहीं बता पा रहा कि हथियार इंदौर में किससे लिए और किसे सौंपने वाला था।

पुलिस के अनुसार आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहा है, जिससे उसके पीछे बड़े नेटवर्क की आशंका और गहरी हो गई है। माना जा रहा है कि यह गिरोह अलग-अलग राज्यों में अवैध हथियारों की सप्लाई करता है। इंदौर में हथियारों की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से पुलिस किसी बड़ी साजिश की संभावना से भी इनकार नहीं कर रही। डीसीपी ने बताया कि बरामद पिस्टलों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं इनका इस्तेमाल किसी वारदात में तो नहीं हुआ। पुलिस आरोपी के मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की भी जांच कर रही है।

वीडियो कॉल पर फांसी के फंदे पर चढ़ी महिला, नहीं बच सकी जान

इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में 24 वर्षीय मुस्कान ने की आत्महत्या

इंदौर। एरोड्रम थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 24 वर्षीय मुस्कान खेडेकर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्कान ने फंदा लगाने से ठीक पहले अपने पति शिवा को वीडियो कॉल किया था। उस समय शिवा तीन ईमली क्षेत्र में स्थित गोदाम पर काम कर रहा था। कॉल के दौरान मुस्कान ने अपनी आवाज बंद कर दी और फंदे की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर शिवा घबरा गया और तुरंत अपने मालिक को फोन किया। मालिक ने एक परिचित को मौके पर भेजा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मुस्कान की मौत हो गई। मुस्कान और शिवा की शादी को दो वर्ष ही हुए थे। यह उसकी दूसरी शादी थी, जबकि पहले पति की मौत एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके पांच साल के बच्चे को उसने घटना से पहले सुला दिया था। पुलिस जांच में पता चला कि मुस्कान कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। परिवार में लगातार हुई मौतों के कारण वह अवसादग्रस्त चल रही थी। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल आत्महत्या का कारण डिप्रेशन माना जा रहा है, लेकिन मामले की विस्तृत जांच जारी है।

संपादकीय

लैंड पूलिंग : खुशी की चमक फीकी

मप्र की मोहन यादव सरकार के इस स्पष्टीकरण कि उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिए लागू लैंड पूलिंग एक्ट में केवल संशोधन किया गया है, उसे वापस नहीं लिया गया है, के बाद किसानों के चेहरों की खुशी फीकी पड़ गई है। भारतीय किसान संघ और किसानों ने फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि दो दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस विवादित एक्ट की वापसी का ऐलान किया था, लेकिन बाद में न जाने क्या हुआ कि अब इसमें केवल संशोधन की बात कही जा रही है। सीएम ने एक्ट वापसी का वादा आरएसएस और किसानों के दबाव के बाद किया था। लेकिन बुधवार को जारी आदेश से स्पष्ट हुआ कि सरकार ने पूरा एक्ट खत्म नहीं किया है, बल्कि इसकी एक धारा में बदलाव किया है। धारा 52(1) ख के तहत धारा 50(12) क में संशोधन किया है। यानी कानून हटाया नहीं, बस उसके नियमों में संशोधन किया है। उल्लेखनीय है कि लैंड पूलिंग में सरकार किसानों की जमीन लेती, वहां पक्का निर्माण कर आधी जमीन लौटा देती। बदले में मुआवजे का प्रावधान नहीं था। विरोध के बाद सरकार ने इसमें संशोधन किया। नए संशोधन के बाद सरकार 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा देकर विकास योजनाएं बनाएगी। सीएम ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। ऐसा लगता है कि उनसे मिलकर लौटने के बाद बुधवार को सरकार ने नया आदेश जारी किया। इसके मुताबिक किसानों को जमीन का मुआवजा कितना मिलेगा, यह फैसला सरकार ही करेगी। अगर सिंहस्थ क्षेत्र में पक्के निर्माण जैसे सड़क, बिजली, नाली या पानी की टंकी बनते हैं, तो जमीन स्थायी रूप से अधिग्रहित होगी। ऐसे में किसानों को दोगुना मुआवजा मिल सकता है। अस्थायी काम जैसे कच्ची सड़क आदि के लिए कम मुआवजा मिलेगा। किसानों की चिंता यह है कि पक्का निर्माण होने पर वे जमीन देने से मना नहीं कर सकते। किसी को आपत्ति हो तो हाई कोर्ट जाना होगा। इसके अलावा सरकार ने सिंहस्थ क्षेत्र की 2344 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर 'स्पिरिचुअल सिटी' बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए चार क्षेत्र टीडीएस 8, 9, 10 और 11 चिह्नित थे, जिन पर उज्जैन विकास प्राधिकरण का अधिकार था। अब इन चारों स्कीमों की जमीन का हक फिर किसानों के पास होगा। उधर भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने आदेश को गोल-मोल बताया है। किसानों की मांग थी कि सिंहस्थ क्षेत्र में लैंड पूलिंग एक्ट पूरी तरह खत्म किया जाए। टीडीएस 8, 9, 10 और 11 की गजट नोटिफिकेशन रद्द किए जाएं। किसानों पर दर्ज सभी केस वापस हों। सिंहस्थ क्षेत्र में कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाए। लेकिन सरकार ने उसे नहीं माना। यही नहीं, कितनी जमीन पर निर्माण होना है, फैसला सरकार करेगी। निर्माण के लिए 70 हेक्टेयर के आसपास जमीन की जरूरत है। इसमें 23 हेक्टेयर सरकारी जमीन है। बाकी 45-50 हेक्टेयर निजी जमीन का अधिग्रहण 2013 के कानून के तहत होगा। उल्लेखनीय है कि सिंहस्थ से पहले सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद मेला क्षेत्र में अतिक्रमण रोकना है। अभी यहां 'मध्यभारत सिंहस्थ मेला एक्ट 1955' लागू है। जब मेला क्षेत्र में नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, तो आगे पक्के निर्माण को रोकने के लिए सरकार नए एक्ट में सख्त आर्थिक दंड का प्रावधान जोड़ेगी। वैसे भी 12 साल में एक बार होने वाले सिंहस्थ के लिए स्थायी निर्माण कराने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सिंहस्थ समाप्ति के बाद बाकी समय इनका क्या उपयोग होगा, कौन इसका संधारण करेगा?

नजरिया

अवधेश कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

समता, सामाजिक न्याय, विकास व हिंदुत्व का परिणाम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जद यू भाजपा सरकार ने व्यापक जन समूह के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे असंतुष्ट होकर उसे सत्ताच्युत कर दें। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला विपक्ष सरकार में रहकर या विरोधी समूह के रूप में जनसमूह में सरकार विरोधी आलोड़न पैदा नहीं किया कि इन्हें सत्ता देने के लिए एकजुट हो जाए। वास्तव में चुनाव के दौरान लोगों से बात करने पर साफ दिखाई देता था कि नीतीश सरकार को लेकर प्रदेश स्तर पर कोई सामूहिक असंतोष है ही नहीं। तीसरी शक्ति के रूप में खड़े होने की कोशिश कर रही जन सुराज को गांव तक लोग अवश्य जानते थे, दल के रुप में जनसुराज के सीधे मतदाता नहीं मिलते थे। कुछ उम्मीदवारों के समर्थन में अवश्य लोग थे। महिलाओं का मत पुरुषों की तुलना में अधिक होना चुनाव परिणाम का बहुत बड़ा संकेतक था। अगर संक्षेप में इन्हीं बिंदुओं को आधार बना दें तो चुनाव परिणाम आसानी से समझ आ जाएगा।

तो बिहार के मतदाताओं ने एकपक्षीय जनादेश दिया। यह धारणा पिछले डेढ़ दशकों में ध्वस्त हो चुकी है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान होने का अर्थ सत्ता विरोधी रुझान है। मतदान घटने या बढ़ने से सत्ता के जाने या बने रहने का सामान्यतः कोई सीधा संबंध नहीं रहा। बिहार में 66.91 प्रतिशत अभूतपूर्व मतदान ने इसे फिर साबित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम ने केवल उन लोगों को चौंकाया होगा जो वस्तुस्थिति से दूर कल्पनालोक में थे या भांपते हुए भी परिणाम आने तक सच स्वीकारने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस अब राहुल गांधी के नेतृत्व में पराजय वाले परिणामों को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। उन्हें महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक तक में वोट चोरी दिखा और बिहार में भी यही होगा। बिहार की राजनीति की पिछले तीन दशकों के साथ वर्तमान स्थिति समझने वालों के लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक परिणाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जद यू भाजपा सरकार ने व्यापक जन समूह के विरुद्ध ऐसा कुछ नहीं किया जिनसे असंतुष्ट होकर उसे सत्ताच्यूत कर दें। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला विपक्ष सरकार में रहकर या विरोधी समूह के रूप में जनसमूह में सरकार विरोधी आलोड़न पैदा नहीं किया कि इन्हें सत्ता देने के लिए एकजुट हो जाए। वास्तव में चुनाव के दौरान लोगों से बात करने पर साफ दिखाई देता था कि नीतीश सरकार को लेकर प्रदेश स्तर पर कोई सामूहिक असंतोष है ही नहीं । तीसरी शक्ति के रूप में खड़े होने की कोशिश कर रही जन सुराज को गांव तक लोग अवश्य जानते थे, दल के रुप में जनसुराज के सीधे मतदाता नहीं मिलते थे। कुछ उम्मीदवारों के समर्थन में अवश्य लोग थे। महिलाओं का मत पुरुषों की तुलना में अधिक होना चुनाव परिणाम का बहुत बड़ा संकेतक था। अगर संक्षेप में इन्हीं बिंदुओं को आधार बना दें तो चुनाव परिणाम आसानी से समझ आ जाएगा।

यह परिणाम एक साथ प्रदेश और केंद्र के शासन की निरंतरता, विकास, हिंदुत्व, लैंगिक समानता सहित सामाजिक न्याय के कदमों की सम्मिलित परिणति है। सम्पूर्ण विपक्ष विशेषकर कांग्रेस द्वारा नकारात्मक व्यवहारों के विरुद्ध जन प्रतिक्रिया भी इसमें शामिल है। गठबंधनों वाले चुनावी संघर्ष में प्रदर्शन इस पर निर्भर करता है कि आप एकजुट होकर एक स्वर में बोलते हुए किस तरह मुद्दों, वक्तव्यों और रणनीति पर एकरूपता प्रदर्शित करते हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पहले दिन से एकजुट दिखाई दिया। थोड़े बहुत मतभेद होते हुए भी इन्होंने सीटों का बंटवारा कर सार्वजनिक घोषणा कर दी। विपक्षी गठबंधन जिसे महागठबंधन कहा गया था उसकी कोई बैठक सार्वजनिक रूप से होती नहीं दिखी। सभी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। ऐसा संदेश निकला कि केवल भाजपा को हराने के नाम पर साथ हैं अन्यथा उनके बीच एकजुटता नहीं है। तेजस्वी यादव को नेता घोषित करने में भी काफी देरी हुई क्योंकि कांग्रेस इसे स्वीकारने को तैयार नहीं थी। तेजस्वी के नेतृत्व की घोषणा के समय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं प्रदेश अध्यक्ष तक वहां उपस्थित नहीं थे। अशोक गहलोत और पवन खेड़ा की उपस्थिति में घोषणा हुई। दूसरी ओर भाजपा ने लगातार घोषणा किया कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं।

विपक्षी गठबंधन को पिछले चुनाव में चिराग पासवान के लोजपा आर के विद्रोही हो जाने का लाभ मिला था। अगर लोजपा 137 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर भी राजद कांग्रेस को सत्ता तक नहीं पहुंचा सकी और इस बार वह राजग में है। उपेंद्र कुशवाहा का रालोमो पिछली बार अलग गठबंधन में था। तो राजग ने दो सामाजिक आधारों वाले नेता को जोड़ा और दूसरी ओर केवल एक मुकेश साहनी की वीआईपी थी। मुकेश सहनी संपूर्ण सहनी समाज का प्रतिनिधित्व कर लेंगे शायद यही सोचकर उन्हें उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया। परिणाम बताते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस की पूरी रणनीति वोट चोरी तथा चुनाव आयोग के विरुद्ध अभियानों तक सीमित रहा। बिहार में कहीं ऐसे लोग नहीं निकले जिन्होंने जानबूझकर मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप लगाया इसलिए जमीन पर यह मुद्दा नहीं था बल्कि इसके विपरीत प्रतिक्रिया थी। कांग्रेस उम्मीदवारों तक ने इसे मुद्दा नहीं बनाया। जो है नहीं उसे आप प्रमुख मुद्दा बनाकर चुनाव अभियान चलाएंगे तो परिणाम क्या आएगा?

महिलाएं ज्यादा संख्या में किनके लिए वोट डालने निकलीं थीं? महिलाओं की भागीदारी 71.6 प्रतिशत रही। कुल 2.51 करोड़ महिलाओं ने मत डाला, जबकि पुरुष मतदाता 2.47 करोड़ रहे। महिलाओं का मत पुरुषों से 4.34 लाख अधिक था। 2020 में 2.08 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया था। इसकी तुलना में महिलाओं का मत 43 लाख अधिक रहा। यह यूं ही नहीं हुआ श। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने आरंभिक दिनों से महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के उद्देश्य से साइकिलें, पुस्तकें, वस्त्र, स्कॉलरशिप दिए गए। स्थानीय शासन में उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण मिला और बाद में सरकारी नौकरियों में भी। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर कई कल्याणकारी कार्यक्रमों में महिलाओं को प्रमुखता दी। इन सबसे बिहार की महिलाओं का मनोविज्ञान बदला हुआ है। जिन बच्चियों को 2005-10 में पढ़ाई की सुविधा मिली अगर वह 15 से 20 वर्ष की थीं तो आज 35 से 40 वर्ष की हो चुकी हैं और उनकी दूसरी पीढ़ी को लाभ मिल रहा है। जीविका दीदी से लेकर छोटे-छोटे रोजगार के लिए 10 हजार रुपए खाते में जाना इन्हीं सबका अगला कदम था। इनकी आप जीतनी आलोचना करिए लेकिन महिलाओं के अंदर घर में रहकर छोटे-छोटे काम कर थोड़े धन उपार्जन की प्रवृत्ति गांव में देखी जा सकती है। यह राजग का ऐसा वोट बैंक है जिसे तोड़ना आसान नहीं।

भारत के किसी भी चुनाव परिणाम का आकलन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुत्व और राष्ट्र भाव के आधार पर भाजपा का एक ठोस जनाधार पूरे देश में है। वह चुनाव हारे या जीते एक निश्चित मत उसके खाते जाना ही है। बिहार में हर जाति के लोग लोगों में भाजपा के ऐसे मतदाता सामने आते थे। हमारी समस्या यह है कि हम मान कर चलते हैं कि बिहार में जाति के परे चुनाव का विश्लेषण नहीं हो सकता। जातियां एक कारक हैं। इस बार डरावना और शर्मनाक तस्वीर बिहार में दिख रही थी जब छोटी-छोटी जातियों का समूह बनाकर नेता अपने को जनाधार वाला साबित कर रहे थे। एक समय बिहार में पिछड़े -अगड़ों की बात होती थी, इस बार ऐसा लगता था जैसे पूरा बिहार इतने जातीय आधारों में बंट चुका है कि अब इसका बाहर निकलना असंभव है। चुनाव परिणाम इस मायने में आशाजनक संकेत है। मतदाताओं के एक बड़े वर्ग ने जातियों से ऊपर उठकर भूमिका निभाया तभी ऐसा परिणाम आया। इसका संकेत और संदेश ऐसे नेताओं के सामने स्पष्ट है। सभी दलों के नेताओं को समझना चाहिए कि हम आप किसी जाति से हहैं पर 24 घंटे हमारे अंदर केवल जाति भाव नहीं रहता। वैसे भी बिहार में जिन्हें अगड़ी कहा जाता था उन्होंने पिछड़ों-दलितों के साथ लगभग अपने सामान्य संबंध बनाए हैं। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनावों तक एक दूसरे के लिए काम करते हैं मत देते हैं। आपस के खान-पान भी काफी बढ़े हैं। यह दुर्भाग्य है कि राजनीतिक नेताओं ने इस आशाजनक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की जगह वोट के लिए जातीय भाव को और सशक्त करने की कोशिश की। निष्पक्षता से अध्ययन करें तो निष्कर्ष निकलेगा कि बहुत बड़े वर्ग के लिए चुनाव में जाति कारक नहीं था। अगर यादवों की एक छोटी संख्या ही अररिया,बिस्फी, केवटी, किसनगंज, पूर्णिया जैसे स्थानों पर भाजपा या राजग उम्मीदवारों को मत दे रहा था तो साफ है कि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ाई जा सकती है। वस्तुतः बिहार चुनाव परिणाम ने साबित किया है कि राजनीतिक तत्व और शासकीय नीतियों में स्त्री पुरुष समता को केंद्र बनाकर सामाजिक न्याय, विकास, कानून व्यवस्था तथा हिंदुत्व के साथ राष्ट्रीय भाव का समायोजन हो तो धीरे-धीरे बहुसंख्यक जातीय परिधि को तोड़कर आगे आ सकता है।

सामयिक

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

राजनीतिक कुलों में संग्राम

बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार के बाद दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार में वर्चस्व का संग्राम छिड़ गया है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज खान को चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। परिवार के सदस्यों में मानसिक विकृति किस हद तक होती है, इसका उदाहरण देते हुए रोहिणी ने कहा है कि 'मुझे गालियां देते हुए कहा गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। इसके बदले में मैंने करोड़ों रुपए और चुनावी टिकट लिए। मुझे अब अपनी उदारता पर पछतावा हो रहा है। मेरा देश की सभी बेटियों से अनुरोध है कि जब आपके मायके में कोई बेटा या भाई हो तो भूलकर भी अपने पिता को नहीं बचाएं।' लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव भी रोहिणी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि 'यदि बहन रोहिणी का माता-पिता ने किसी भी भी तरह का मानसिक उत्पीड़न दिया है तो उसकी जांच होनी चाहिए।' तेजप्रताप ने यहां तक कह दिया कि जयचंदों को जमीन पर दफन कर देंगे। राज और राजनीतिक वंशों में देखने में आया है कि जब तक वे प्रगति कर रहे होते हैं, तब तक उनमें एकता बनी रहती है, लेकिन पतन के समय ये कुनबे बिर जाते हैं। कुदरत का यह ऐसा जाल है कि वह वंशों के डीएनए में ही अलगाव के बीच बो देता है।

भारतीय लोकतंत्र की जमीन पर जड़ें जमाते राजनीति के वंश-वृक्ष देश की संवैधानिक संप्रभुता की जड़ों में मट्ठा घोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस समेत हरेक क्षेत्रीय राजनीतिक दल में राजनीतिक उत्तराधिकार और वंशवाद को राजनीति के फलक पर स्थापित करने की होड़ लगी है। भाजपा में भी वंशवाद का रोग पनपा हुआ है। वामदलों को जरूर हम अपवाद के रूप में देख सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे दलों की मानसिकता पर कुठाराघात करते हुए उन्हें लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना का विरोधी बताते हुए हमेशा हमलावर रहे हैं। उन्होंने इस प्रवृत्ति को सामंतशाही की संरक्षक और लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं के लिए घातक बताया है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि विकृत वंशवादी मनोवृत्ति के चलते बहुदलीय शासन प्रणाली, एकतंत्रीय व्यक्तिवाद की गिरफ्त में आती जा रही है। इस नाते देश के प्रमुख राष्ट्रीय दल संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को एकध्रुवीय बनाने की कोशिश में लगे रहे हैं। कांग्रेस ने तो समूची राजनीति को राहुल गांधी और क्षेत्रीय दलों ने परिवार के मुखियाओं पर केंद्रित कर दी है। जबकि संवैधानिक व्यवस्था बहुदलीय है। लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने का यह खेल न तो देश की बुनियादी समस्याएं भूख, अन्याय और असमानता से लड़ने में कामयाब हो सकती हैं और न ही सीमाई संप्रभुता व आंतरिक समस्याओं से निपटने में दो-चार हो सकती हैं? दरअसल आसानी से मिला राजनैतिक उत्तराधिकार का वैभव व्यक्ति की मानसिकता को सुविधा-भोगी और व्यक्तिवादी महत्वाकांक्षा को बढ़ाने का काम करता हैं। वह राजसी भोग-विलास में भी लग जाता है। प्रजातंत्र में यह स्थिति अपरोक्ष रूप से सामंती मूल्यों को स्थापित करने वाली है।

स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आए संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के आदर्शों के साथ देश को एक मजबूत राष्ट्र में गूंथने की परिकल्पना की गई थी। किंतु जब 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ तो संविधान में दर्ज आदर्श को पलीता लगाने का काम कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दलों ने धर्म और जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन और वोट मांग कर किया। अब आजादी के 78 साल बाद भी धर्म और जाति तो अपनी जगह कायम हैं ही, खरपतवार की तरह वंशवादी ऐसे बरगदी वृक्ष भी उग आए हैं,जो प्रजातांत्रिक मूल्यों और भावनाओं को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। बुंदेलखंण्ड में एक कहावत प्रचलित है कि चंबल नदी की गहराई एक दर्जन खाटों की बान से भी नहीं नापी जा सकती ? लेकिन प्रजातंत्र की मिट्टी में वंशवाद की जड़ें जितनी गहरी होती जा रही हैं,उन्हें तो दो दर्जन खाटों के बान से भी नहीं नापा जाना मुश्किल है ?

राजनैतिक वंशवाद का वास्ता ग्वालियर क्षेत्र में सिंधिया राजघराने से आज भी मजबूती से जुड़ा है। आजादी की लड़ाई में असहयोग के बावजूद राज-परिवार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वंशवाद से नाता टूटने की फिलहाल कोई उम्मीद ही नहीं हैं। विजयाराजे सिंधियां से शुरू हुआ वंशवादी यह जीवाणु उनके बेटे माधवराव सिंध्यि और बेटियों वसुंधरा राजे व यशोधरा राजे के बाद इनकी तीसरी पीढ़ी ज्योतिरादित्य और दुष्यंत सिंह के जरिए भी अवतरित होता चला गया है। अब ज्योतिरादित्य अपने पुत्र महाआर्यमन को मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जरिए राजनीति की सीढ़ियां चढ़ाने में लगे है। एक समय इस वंश की खूबी यह रही कि यह देश के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस में समान रूप से स्थापित रहा, लेकिन अब ज्योतिरादित्य के भाजपा में आने के बाद पूरा कुनबा भाजपाई हो गया है।

इन दो वंश-वृक्षों से उत्प्रेरित होकर कालांतर में कई राजनेताओं के परिवार इस डगर पर चल निकले हैं। इसमें वे लोहियावादी भी शामिल हैं,जो कई दशकों तक विवाद को कोसते हुए इन्हें लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा बताते रहे। लेकिन क्षेत्रीय दलों के प्रमुख बनने और सत्ता की बागडोर हाथ में आते ही लालू प्रसाद, मुलायम सिंह और रामविलास पासवान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। लालू को जब चारा घोटाले के मामले में बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने की नौबत आई,तो उन्हें अपना राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा एक भी होनहार नेता नहीं दिखाई दिया जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने की काबिलियत रखता हो ? आखिरकार यह योग्यता उन्हें अपनी निरक्षर धर्मपत्नी रावड़ी देवी में ही दिखाई दी। अंततः लालू ने प्रजातांत्रिक राज्यसत्ता रावड़ी को मनोनीत करके हस्तांतरित कर दी। स्वतंत्र भारत में राज्यसत्ता के पारिवारिक उत्तराधिकारी को ही हस्तांतरित किए जाने की यह मनोवृति सबसे शर्मनाक स्थिति रही है। बाद में लालू के दो पुत्र और दो पुत्रियां राजनीति में सीधे दखल देने लग गईं। किंतु 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू कुनबे की कलह सड़क पर आ गई। दक्षिण में भी वंश-वृक्ष खूब फल-फूल रहे हैं। आठ दशक पुराने क्रांतिकारी द्रविड आंदोलन और हिन्दी के विरोध की कोख से जन्मी द्रविड मुनेत्र कशघम यानी द्रमुक भी वंशवाद की राह पर है। एम करुणानिधि की राजनैतिक विरासत का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन है, इस सवाल को लेकर उनके दोनों बेटों में खूनी जंग भी छिड़ चुकी है। हालांकि बड़े बेटे एमके अलागिरी की बजाए करुणानिधि ने छोटे बेटे एमके स्टालिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसलिए पार्टी, तमिलनाडू और राज्य सत्ता की कमान स्टालिन के हाथ है। उनकी बेटी कनिमोझी भी सासंद हैं। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में वे जेल भी जा चुकीं हैं। हालांकि करूणानिधि और उनका दल साम्यवाद से प्रभावित रहा है। मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, वह प्रजातंत्र में कुनबापरस्ती का विरोध करता है, लेकिन करुणानिधि का वंश इसी कुनुबापरस्ती की गिरफ्त में है। तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती अविवाहित हैं, बावजूद वंशवादी मानसिकता के चलते अपने भतीजों को आगे बढ़ा रही हैं।

तेलंगाना में केसीआर का उत्तराधिकारी कौन हो इसे लेकर भाई-बहन आपस में टकरा रहे हैं। बेटी कविता 2023 के शराब घोटाले में गिरफ्तार हुई तो भीतर का संघर्ष सड़क पर आ गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे के अलग होने के बाद 2022 में शिंदे की बगावत ने शिवसेना के दो फाड़ कर दिए। इस अलगाव की वजह से बाल ठाकरे की विरासत कमजोर हुई तो भाजपा सत्ता के सिंहासन पर जा बैठी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की मौत के बाद 2023-24 में पैतृक संपत्ति पर अधिकार को लेकर जगन और उर्मिला के बीच विवाद सामने आया और दोनों अलग-अलग दलों में पहुंच गए। महाराष्ट्र में शरद पवार की राजनीतिक विरासत पर रस्साकशी के बाद 2023 में अजीत पवार भाजपा-शिंदे सरकार में शामिल हो गए, जिसके चलते पार्टी दो हिस्सों में विभाजित हो गई, इस विभाजन के साथ ही महाराष्ट्र में कई सीटों पर कांग्रेस-शिवसेना और अन्य गठबंधनों के साथ समीकरण बदल गए। जिसका नतीजा कांग्रेस शरद पवार और शिवसेना को भुगतना पड़ा।

आज देश में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह निर्मित हो गई है कि एक जमाने में वंशवाद के जो प्रबल विरोधी थे और जिन्हें गांधी परिवार फूटी आंख भी नहीं सुहाता था, वे इसके समर्थक व निष्ठावान अनुयायी हो गए हैं। इसी कारण राजनीतिक वंशवाद ने अब एक ब्रांड का रूप धारण कर लिया है। आम जनता को इससे सचेत होने की जरूरत है। ब्रिटेन के लोकतंत्र का उल्लेख करते हुए दार्शनिक रूसो ने कहा था, 'इग्लैंण्ड की जनता समझती है कि वह आजाद है,तो यह उसका भ्रम है। जनता की आजादी केवल वहीं तक है,जहां तक वह माननीय सांसदों का चुनाव करती है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जनता को गुलाम कैसे बनाए रखा जाए, इस दूषित मानसिकता का दुश्चक्र तुरंत घूमना शुरू हो जाता है' । भारत में यह कथन सत्य के निकट है।

बुजुर्ग- हमारी जड़ें, छाया और मार्गदर्शक

दृष्टिकोण

श्याम कोलारे

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

समाज की खूबसूरती उसके विविध रंगों में बसती है, और उन रंगों में सबसे पवित्र, सबसे उज्ज्वल रंग है– बुजुर्गों का अस्तित्व। बुजुर्ग सिर्फ उम्र से बड़े नहीं होते, बल्कि अनुभव, समझ, संयम और त्याग में भी उतने ही विशाल होते हैं। जीवन की लंबी यात्रा तय करने के बाद वे हमारे लिए ज्ञान का वह खजाना बन जाते हैं, जिसकी चमक किसी भी मुश्किल घड़ी में राह दिखाने में सक्षम होती है। हम अक्सर कहते हैं कि 'हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए,' परंतु सम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार, हमारे धैर्य, हमारी विनम्रता और हमारे प्रेम से व्यक्त होता है। बुजुर्ग वे नींव के पत्थर होते हैं जो खुद को जमीन में दबाकर, अंधेरे में रहकर भी, हमारी जिंदगी की इमारत को मजबूती देते हैं। वे हमें वह आधार प्रदान करते हैं जिस पर हम अपना भविष्य, अपना जीवन और अपने सपने खड़े करते हैं। वे हमारे लिए हर कदम पर छाया बने रहते हैं–कभी पिता की तरह कठोर पर सुरक्षा देने वाले, कभी माँ की तरह ममता से लबालब, कभी दादा-दादी की तरह कहानियों में जीवन की सीख छिपाए हुए, और कभी गुरु की तरह शांत स्वर में दिशा दिखाते हुए।

बुजुर्गों का एक-एक अनुभव एक पुस्तक के समान होता है। जहाँ हम युवा लोग अक्सर जल्दबाज़ी या अधीरता में गलत फैसले ले बैठते हैं, वहीं बुजुर्गों की दूरदर्शिता, सतर्कता और परिपक्वता हमें सही मार्ग पर ले आती है। उन्होंने जिंदगी को नज़दीक से देखा है– उसके उतार-चढ़ाव, संघर्ष और खुशियों को महसूस किया है। इसीलिए उनकी सीख हमेशा हितकारी होती है। उनकी उपस्थिति मात्र से घर में एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। बुजुर्गों की धीमी आवाज़ में एक आश्वासन छिपा होता है, जैसे कह रहे हों–'चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।' उनके आशीर्वाद की ताकत इतनी प्रबल होती है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे सामने छोटी लगने लगती है। जब कोई बुजुर्ग अपनी कांपती हुई हथेलियों से सिर पर हाथ रखता है, तो वह स्पर्श सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच, एक शक्ति, एक आत्मविश्वास होता है।

दुर्भाग्य से आधुनिक जीवन की तेज़ रफ्तार में कई बार लोग बुजुर्गों को बोझ समझ बैठते हैं। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जिस सुविधा, जिस सुख, जिस स्थिरता में खड़े हैं, वह उन्हीं के त्याग और संघर्षों से संभव हुआ है। उन्होंने अपने जीवन की खुशियाँ त्यागकर हमारे लिए रास्ते बनाए, अपनी इच्छाएँ रोककर हमारी इच्छाओं को पूरा किया, और अपने सपनों को पीछे रखकर हमारे सपनों को आकार दिया। वो हाथ, जिन पर आज झुर्रियाँ दिखाई देती हैं, कभी हमारे लिए काम करते-करते थकते नहीं थे। उनकी धीमी चलती कदमों में कभी वह तेजी थी जिसने परिवार को आगे बढ़ाया था। उनकी कमज़ोर होती आँखों में कभी वह चमक थी जिसने हमें पहली बार दुनिया दिखाई थी। इसलिए, यदि आज वे हमसे थोड़ा सहारा चाहते हैं, थोड़ा समय चाहते हैं, थोड़ा स्नेह चाहते हैं, तो इसमें अहसान नहीं–यह हमारा कर्तव्य है।सम्मान केवल खड़े होकर प्रणाम करने का नाम नहीं, बल्कि उनके साथ बैठने, उनकी बातों को धैर्य से सुनने, उनकी आवश्यकताओं को समझने और उन्हें प्यार देने का नाम है।

बुजुर्गों का सम्मान करना केवल उनका नहीं, बल्कि अपने संस्कारों का सम्मान करना है। यह वह विरासत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाना चाहिए। जब बच्चे अपने घर में बुजुर्गों को सम्मानित होते देखते हैं, तभी वे स्वयं संस्कारित होते हैं और भविष्य में अपने माता-पिता के लिए वही सम्मान लेकर बड़े होते हैं। बुजुर्ग घर की छत की तरह होते हैं–जो खुद धूप और बारिश सहकर परिवार को बचाते हैं। एक छत कितनी भी पुरानी हो जाए, उसकी अहमियत कम नहीं होती। उसी तरह बुजुर्गों की उम्र भले ही बढ़ जाए, पर उनकी महत्ता कभी कम नहीं हो सकती।उनके प्रति थोड़ा-सा प्रेम, थोड़ा-सा धैर्य और थोड़ा-सा समय उनके जीवन के लिए अनमोल है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा अग्निबाण पब्लिकेशन, 121, देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा 'उरतृप्त'

लेखक व्यंग्यकार हैं।

सादगी का बाज़ार भाव

माधवी एक साधारण-सी लड़की थी–इतनी साधारण कि उसकी सादगी बाज़ार में एक नया 'ट्रेंड' बन सकती थी। उसका सपना था कि वह देश के किसी प्रतिष्ठित कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करे, ताकि उसे एक 'स्थिर, बौद्धिक करियर' मिल सके। 'स्थिर' इसलिए, क्योंकि अस्थिरता तो केवल ग़रीबों के लिए होती है, और 'बौद्धिक' इसलिए, क्योंकि मध्यम वर्ग को अपनी सांसारिक कमाई को 'महान उद्देश्य' का चोला पहनाना ज़रूरी होता है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था–यानी, किस्मत ने भी उसे धोखा दिया। एक दिन, एक सांस्कृतिक कार्यक

पर्यावरण

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

क्या भारत को चाहिए एक व्यापक 'प्रदूषण कर'?

प्रदूषण कर का विचार नया नहीं, परन्तु इसकी आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि जब कोई उद्योग, वाहन या गतिविधि प्रदूषण फैलाती है तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, न कि केवल उसे जो प्रदूषण फैला रहा है। यह बाज़ार व्यवस्था की वह गंभीर विफलता है जिसे 'बाह्य लागत' कहा जाता है—अर्थात् नुकसान तो समाज को होता है, पर उसका मूल्य न तो वस्तु की कीमत में जुड़ता है, न ही प्रदूषण फैलाने वाला उसे भरता है। ऐसे में 'प्रदूषण कर' इसी असंतुलन को सुधारने का प्रयास करता है, जहाँ जो जितना अधिक प्रदूषण फैलाए, वह उतनी अधिक आर्थिक कीमत चुकाए।

भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ तेज आर्थिक विकास और बिगड़ते पर्यावरण के संकट के बीच संतुलन बनाना अत्यंत कठिन चुनौती बन गया है। शहरों की हवा दिन-प्रतिदिन जहरीली होती जा रही है, नदियाँ औद्योगिक कचरे से भर रही हैं, भूमिगत जल स्तर घट रहा है, ठोस कचरे के पहाड़ महानगरों की पहचान बनते जा रहे हैं, वहीं जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या अब भारत को प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रत्यक्ष आर्थिक दंड लगाने–अर्थात् विस्तृत 'प्रदूषण कर' लागू करने–की आवश्यकता है?

प्रदूषण कर का विचार नया नहीं, परन्तु इसकी आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। अर्थशास्त्र में यह माना जाता है कि जब कोई उद्योग, वाहन या गतिविधि प्रदूषण फैलाती है तो उसका दुष्परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, न कि केवल उसे जो प्रदूषण फैला रहा है। यह बाज़ार व्यवस्था की वह गंभीर विफलता है जिसे 'बाह्य लागत' कहा जाता है–अर्थात् नुकसान तो समाज को होता है, पर उसका मूल्य न तो वस्तु की कीमत में जुड़ता है, न ही प्रदूषण फैलाने वाला उसे भरता है। ऐसे में 'प्रदूषण कर' इसी असंतुलन को सुधारने का प्रयास करता है, जहाँ जो जितना अधिक प्रदूषण फैलाए, वह उतनी अधिक आर्थिक कीमत चुकाए।

भारत में कोयले पर लगाया गया 'स्वच्छ ऊर्जा उपकर' इसका एक प्रारंभिक स्वरूप था, परंतु आज देश में वायु, जल, ध्वनि, ठोस कचरा और औद्योगिक उत्सर्जन का ऐसा मिश्रित संकट है कि केवल किसी एक क्षेत्र पर कर लगाना पर्याप्त नहीं। आवश्यकता एक सर्वसमावेशी और वैज्ञानिक पद्धति से तैयार प्रदूषण कर की है, जो प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ विकल्पों को बढ़ावा देने में सहायक हो।

प्रदूषण कर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह प्रदूषण को महँगा बनाता है और स्वच्छता को सस्ता। जब किसी उद्योग को प्रति इकाई उत्सर्जन पर कर देना पड़ेगा, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसी तकनीक अपनाने की ओर अग्रसर होगा जो कम प्रदूषण करे। यूरोप जैसे क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है जहाँ कार्बन-आधारित दंड के बाद ऊर्जा-संरक्षण और हरित तकनीक का उपयोग अत्यधिक बढ़ा। भारत में भी यह परिवर्तन संभव है, बशर्ते नीति दीर्घकालिक, पारदर्शी और लक्ष्य-उन्मुख हो।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत को आने वाले वर्षों में पर्यावरण-रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी। नदियों की सफाई, स्वच्छ परिवहन व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा हरित भवनों के विकास पर अत्यधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी। ऐसे में प्रदूषण कर एक स्थायी और अनुमानित राजस्व स्रोत बन सकता है, जिसे एक स्वतंत्र 'हरित निधि' के माध्यम से केवल पर्यावरण संरक्षण पर व्यय किया जा सकता है।

वैश्विक स्तर पर भी प्रदूषण कर का महत्व बढ़ रहा है। कई विकसित देश अब उन आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगा रहे हैं जो अधिक प्रदूषणकारी स्रोतों से बनती हैं। यदि भारत घरेलू स्तर पर प्रदूषण पर उचित कर लागू करता है, तो भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाज़ारों में अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सकती है। इस प्रकार प्रदूषण कर केवल पर्यावरण-हित में नहीं, बल्कि भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा की रक्षा में भी सहायक सिद्ध हो सकता है।

परंतु इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रदूषण कर गरीबों पर भारी पड़ सकता है? यह चिंता बिल्कुल वास्तविक है। यदि ईंधन और बिजली की लागत बढ़ेगी, तो उसके साथ ही परिवहन, खाद्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। इसका सीधा प्रभाव निम्न-आय वर्ग पर पड़ता है, जिनके पास विकल्प सीमित होते हैं। इसलिए प्रदूषण कर को न्यायपूर्ण बनाने के लिए यह अनिवार्य होगा कि निम्न-आय वाले परिवारों को प्रत्यक्ष नकद सहायता, ऊर्जा सब्सिडी और रसोई गैस जैसी आवश्यकताओं पर राहत दी जाए।

उद्योग जगत की चिंताएँ भी कम नहीं। विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग ऊर्जा-प्रधान होते हैं और किसी भी अतिरिक्त कर का प्रभाव उनकी लागत पर पड़ता है। अतः प्रदूषण कर को चरणबद्ध ढंग से लागू करना होगा–पहले बड़े उद्योगों पर, फिर धीरे-धीरे छोटे उद्योगों को तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ इस दायरे में लाना होगा। हरित मशीनरी पर अनुदान, ब्याज रहित ऋण, और तकनीकी उन्नयन के लिए मार्गदर्शन इस परिवर्तन को सुगम बना सकते हैं।

भारत की प्रशासनिक क्षमता भी एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रदूषण का सटीक मापन, डेटा की विश्वसनीयता और निगरानी तंत्र की पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक होगी। छोटे उद्योगों और गैर-प्रमाणित स्रोतों की निगरानी आज भी चुनौतीपूर्ण है। यदि उत्सर्जन मापन ही विश्वसनीय न हो, तो कर प्रणाली पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को आधुनिक सेंसर-तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, डिजिटल उत्सर्जन-पंजीकरण तथा रियल-टाइम निगरानी प्रणाली को मजबूत करना होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रदूषण कर की सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सरकार इसके राजस्व का उपयोग कहाँ करती है। यदि यह धन सामान्य बजट में विलीन हो गया, तो जनता में अविश्वास बढ़ेगा और नीति का उद्देश्य कमजोर पड़ेगा। इसके लिए एक स्वतंत्र 'हरित कोष' का गठन आवश्यक है, जो केवल प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा, हरित परिवहन और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों पर व्यय हो तथा जिसकी वार्षिक लेखा-परीक्षा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।

राजनीतिक दृष्टि से यह एक साहसिक कदम होगा। किसी भी प्रकार की मूल्य-वृद्धि जनता के बीच असंतोष उत्पन्न कर सकती है। परंतु यह भी सत्य है कि पर्यावरणीय संकट अब इतना गंभीर हो चुका है कि उससे निपटने के लिए कठोर, दीर्घकालिक और दूरदर्शी आर्थिक सुधार आवश्यक हैं। भारत की युवा पीढ़ी सुरक्षित जल, स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन की मांग कर रही है। इस मांग को नज़रअंदाज़ करना अब संभव नहीं।

अंततः यह कहा जा सकता है कि प्रदूषण कर भारत के लिए केवल राजस्व-संग्रह का साधन नहीं, बल्कि एक व्यापक हरित परिवर्तन की दिशा में आवश्यक कदम है। इसे न्यायपूर्ण, पारदर्शी, चरणबद्ध और वैज्ञानिक आधार पर लागू करने से भारत न केवल प्रदूषण कम कर पाएगा, बल्कि अपने विकास मॉडल को भी टिकाऊ, स्वस्थ और पर्यावरण-सम्मत बना सकेगा।

यदि इसे सही नीतिगत ढंग से लागू किया गया, तो यह भारत के इतिहास में वह मोड़ साबित हो सकता है जहाँ देश ने आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को एक-दूसरे का विरोधी नहीं, बल्कि सहयोगी सिद्ध किया।

प्रकाशन बाजार

डॉ.तेज प्रकाश व्यास

(प्रकृति एवं जीव वैज्ञानिक)

मुखी का भारत में शावकों को जन्म देना एपीजेनेटिक बदलाव है

मुखी का यह सफल प्रजनन एक गहन जैव-वैज्ञानिक विजय है, जिसे 'एपिजैनेटिक एडेप्टेशन' के परिप्रेक्ष्य में समझना रोमांचक है: यह घटना सिर्फ संख्यात्मक वृद्धि नहीं है, बल्कि भारतीय धरती के 'हस्ताक्षर' को चीते के जीनोम में शामिल करने का प्रमाण है। मुखी, जो स्वयं भारत में पली-बढ़ी है, उसके शरीर ने भारतीय परिस्थितिकी तंत्र के सूक्ष्म दबावों—तापमान की सीमा, पानी की उपलब्धता, और शिकार की विशिष्ट चुनौतियों के प्रति एक आनुवांशिक स्मृति विकसित की है। इस स्मृति को जैव-वैज्ञानिकी (बायोकैमिकल) भाषा में एपिजैनेटिक (जीन अभिव्यक्ति में स्थायी बदलाव) बदलाव कहते हैं।

मुखी द्वारा पाँच शावकों का जन्म वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह घटना दर्शाती है कि-

आवास की सफलता: कूनो का आवास, भोजन-श्रृंखला और सुरक्षा व्यवस्था चीतों के लिए अत्यधिक अनुकूल है।

स्वाभाविक प्रजनन उछाल: यह एक प्राकृतिक 'प्रजनन उछाल' (natural breeding surge) है, जो किसी भी पुनर्वास परियोजना की सबसे कठिन और सबसे अहम कसौटी होती है।

आत्मनिर्भरता की ओर: यह उपलब्धि स्पष्ट संकेत देती है कि भारत अब आत्मनिर्भर चीता जनसंख्या के लक्ष्य के बेहद करीब है।

इस सफलता से चीतों में आनुवांशिक विविधता बढ़ेगी, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक मज़बूत आधार तैयार करेगी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे 'ऐतिहासिक मील का पत्थर' बताया है।

मुखी का यह सफल प्रजनन एक गहन जैव-वैज्ञानिक विजय है, जिसे 'एपिजैनेटिक एडेप्टेशन' (Epigenetic Adaptation) के परिप्रेक्ष्य में समझना रोमांचक है: यह घटना सिर्फ संख्यात्मक वृद्धि नहीं है, बल्कि भारतीय धरती के 'हस्ताक्षर' को चीते के जीनोम (Genome) में शामिल करने का प्रमाण है। मुखी, जो स्वयं भारत में पली-बढ़ी है, उसके शरीर ने भारतीय परिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के सूक्ष्म दबावों–तापमान की सीमा, पानी की उपलब्धता, और शिकार की विशिष्ट चुनौतियों–के प्रति एक आनुवांशिक स्मृति विकसित की है। इस स्मृति को जैव-वैज्ञानिकी (बायोकैमिकल) भाषा में एपिजैनेटिक (जीन अभिव्यक्ति में स्थायी बदलाव) बदलाव कहते हैं।

'मुखी के पांच शावक, अपनी माँ से विरासत में 'भारतीय जीवन-शक्ति' (Indian Vitality) लेकर पैदा हुए हैं। उनके जीन केवल नामीबिया/दक्षिण अफ्रीका के नहीं हैं, बल्कि उनमें भारत की मिट्टी, मौसम और बैक्टीरिया का एपिजैनेटिक अनुकूलन भी समाहित है। यही कारण है कि ये तीसरी पीढ़ी के शावक, आयातित चीतों की तुलना में भारतीय परिस्थितियों में बेहतर उत्तरजीविता (Survival Rate) और रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) प्रदर्शित करने की क्षमता रखेंगे। मुखी का यह 'देशी' प्रजनन 'प्रोजेक्ट चीता' को सतही सफलता से हटाकर गहरी आनुवांशिकी सफलता के चरण में ले जाता है।'

यह खबर भारत को वैश्विक वन्यजीव संरक्षण के नक्शे पर और भी मजबूती से स्थापित करती है।

अनुभव

पल्लवी सक्सेना

लेखक इंग्लैंड निवासी साहित्यकार हैं।

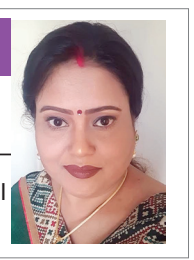

स्मृतियाँ जिनसे हम कभी उबर नहीं पाते

लोग कहते हैं पैसा हो तो सब हो जाता है. पैसे में बड़ी ताकत है. हाँ है, बिल्कुल है. इसमें कोई दौराय नहीं है. लेकिन हम जैसे भावनात्मक इंसानों के लिए हमेशा पैसे से ऊपर भावनायें रहती है क्यूंकि पैसा चाहे जो कुछ भी खरीदने की ताकत क्यों ना रखता हो. लेकिन यादें, प्यार, जज़्बात, कभी नहीं खरीद सकता, विशेष रूप से इस मशीनी युग में तो बिल्कुल भी नहीं. विशेष रूप से स्मृतियाँ हाँ यह कुछ अच्छी बुरी खट्टी मीठी होती है क्यूंकि जीवन भी कभी एक सा नहीं चलता. आमतौर पर लोगों को खराब चीजें ही अधिक याद रहती है. लेकिन मेरे हिसाब से यह अपनी अपनी मनोदशा पर निर्भर करता है. मन अच्छा होगा तो यादें भी अच्छी ही याद आएंगी और मन दुखी होगा तो दुख दर्द ही याद आयेगा.

समय कितना जल्दी बदल जाता है ऐसा लगता है अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है जब हम बच्चे थे. फिर जब होश आता है तो पता चलता है, आज हमारे बच्चे भी अब बड़े हो चुके है. बच्चों के दिमाग में स्मृतियों के रूप में शायद माता पिता हमेशा युवा ही रहते है. अर्थात आज के समय से अधिक युवा किन्तु वैसे देखो तो प्रोढ़ क्यूंकि बच्चों की शादियां आमतौर पर प्रोढ़ अवस्था में ही होती है. लेकिन वास्तविकता हमेशा स्मृतियों से अलग ही होती है. समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है. कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता. कहने को समय का पहिया चलता रहता है और चीजे आती है जाती है, लौटकर फिर से आती भी है. फिर भी उनमें वो महक नहीं होती जिसकी हमें तलाश होती है. फिर वर्तमान में उस समय को जीना कभी तो (नोस्टेलीजिया) महसूस कराता है और कभी (टिक बॉक्स की ज़िन्दगी) ही महसूस होती है.

लोग कहते है पैसा हो तो सब हो जाता है. पैसे में बड़ी ताकत है. हाँ है, बिल्कुल है. इसमें कोई दौराय नहीं है. लेकिन हम जैसे भावनात्मक इंसानों के लिए हमेशा पैसे से ऊपर भावनायें रहती हैं क्यूंकि पैसा चाहे जो कुछ भी खरीदने की ताकत क्यों ना रखता हो. लेकिन यादें, प्यार, जज़्बात, कभी नहीं खरीद सकता, विशेष रूप से इस मशीनी युग में तो बिल्कुल भी नहीं. विशेष रूप से स्मृतियाँ हाँ यह कुछ अच्छी बुरी खट्टी मीठी होती है क्यूंकि जीवन भी कभी एक सा नहीं चलता. आमतौर पर लोगों को खराब चीजें ही अधिक याद रहती है. लेकिन मेरे हिसाब से यह अपनी अपनी मनोदशा पर निर्भर करता है. मन अच्छा होगा तो यादें भी अच्छी ही याद आएंगी और मन दुखी होगा तो दुख दर्द ही याद आयेगा.

खैर मेरी स्मृतियों में भी मेरे माता का वही स्वरूप आज भी जीवित है. जब वो मुझे संभालते थे चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, आज भी वही मम्मी याद आती है जो नयी नयी शादी के बाद घर आयी बेटी के लिए रसोई में उसकी पसंद की चीजे बनाते नहीं थकती थी. शायद बेटियों के लिए मांओं का प्यार उस जमाने में शादी के बाद ही अधिक जगता था. जब वो दूर हो जाती थी. सादी सी रंगीन साड़ी में बड़ी सी बिंदी लगाए आलू की कचौरियाँ बनाती माँ और गरमा गरम कचौड़ी खाने के लालच में हाथ और मुंह दोनों जलाती मैं, एक टपली पड़ती और माँ हाथ में पिठी (अर्थात् कचौड़ी के अंदर भरा जाने वाला मसाला) रखते हुए कहती 'अरे...! रुक जा, दिख नहीं रहा है गरम है बहुत, ले पहले ये खाकर बता मिर्च ठीक है कि और बढ़ाऊं...' क्यूंकि मुझे तीखा बहुत पसंद है. उधर पापा जान बूझकर मुझे छेड़ते और कहते 'बेटा मुझे खुश्की हो रही है तेरा वाला क्रीम लूं क्या थोड़ा सा...!'

शायद उस वक्त वह भी मेरा बचपन ही जी रहे होते थे उनकी स्मृतियों में और कहीं ना कहीं वह यह सुनना चाहते कि मैं लड़ूं झगड़ू उनको बोलूं 'नहीं...!!! यह मेरा है, आप अपना लगाओ ना.'

लेकिन मैंने बड़ी सहजता से कह दिया 'हाँ हाँ लगाओ ना बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है'. वही घर, मोहल्ला, गलियां, बाजार, चौक चौराहे, बहुत याद आते है और जब आँख खुलती है तो मम्मी बूढ़ी हो चुकि है. पापा तो अब इस दुनिया में ही नहीं है. फिर भी इन वृद्धजनों का जीवन और उनकी जीवन शैली हमें कितना कुछ सिखाती है. समय के साथ चलने की इनकी जग दो जहद, शारीरिक रूप से खुद को स्वस्थ रखने की इनकी कर्मठता को सलाम. और एक आजकल के बच्चे है जिनके लिए जीवन का कोई मोल ही नहीं है. बात बात में ऐसा कुछ कर बैठते है. जिसे ना लिखना अच्छा लगता है, ना सुनना, और ना ही पढ़ना.

हालांकि सभी बुजुर्ग एक जैसे नहीं होते. किसी किसी का शरीर उनका बिलकुल भी साथ नहीं दे पाता. लेकिन जीने की और अधिक ललक... हम जैसो के लिए कभी तो हौसला बन जाती है और कभी एक बहुत ही पीड़ा दायक याद जो उनके चले जाने के बाद दिल को बहुत कचोटती है. जैसे अंतिम समय में मेरे पापा के शब्द 'डॉ साहब अब बहुत हुआ अब तो ठीक कर दो...!'

हमनें तो हमारे बड़ो से बहुत कुछ सीखा, समझा जाना, लेकिन यह आज की पीढ़ी ना जाने हम से कुछ सीखती समझती भी है या नहीं, कहना मुश्किल है क्यूंकि हमें भी बाते बहुत देर से समझ आयी और आज भी हम सीख ही रहे है. अपने ही अनुभवों को महसूस कर रहे है. यही सोच सोचकर की माँ ऐसा कहती थी, पापा वैसा कहते थे. जो आज महसूस होता कितना सटीक और सच ही कहते थे. हमारे बुजुर्ग एक तरह से हमारे आने वाले कल का आईना होते है. लेकिन हम उस आईने में खुद को जब ही देख पाते है जब वो हमें छोड़कर चले जाते है. सच ही कहा है किसी ने धन दौलत अपनी जगह है, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ी कोई दौलत नहीं है.

लोग आते है लोग जाते है शेष रह जाती है उनकी स्मृतियाँ, यह वो पंछी है जो बिना पंखों के ही हमें दूर....! बहुत दूर अतीत में कहीं ले जाता है, जहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है वही जीवन दुबारा जिया लिया हम ने, जिसे वर्तमान में जीने को तरसते है. उस अतीत में कोई काश नहीं होता, वर्तमान में लौटते ही उन सभी मधुर स्मृतियों के पंखों में यह काश नाम का तिनका चिपक जाता है और हम खुद को याद दिलाते है, 'आज में जियो, आज में' जो है वर्तमान है. आज से ही आने वाला कल बनेगा. वो कहते है ना 'जो बीत गयी सो बात गयी' लेकिन कुछ बातें बीत जाने के बाद भी बितती नहीं शायद इसी का नाम ज़िंदगी है. कहना कितना आसान होता है कि चलो नयी यादें बनाते हैं. कई हद तक हम बनाते भी है. अपने अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए. लेकिन हम कभी अपनी स्मृतियों से उबर नहीं पाते. कुछ न कुछ हमारे आस पास घटता ही रहता है जो कहीं न कहीं हमारे किसी पुराने अनुभव से जुड़ा होता है. जैसे वो कहते है ना, माता पिता जाकर भी कभी नहीं जाते हमारे चेहरे में, हमारी आदतों में, काम में, बोली में, व्यवहार में, वह हमेशा ही ज़िंदा रहते है.

पीएम आवास के पहले फेज में शहरी सीमा में स्वीकृत हुए 2745 आवास, 2696 पूर्ण

7 हितग्राहियों ने सरेंडर की राशि, 17 को वसूली के लिए जारी किये नोटिस

एस. द्विवेदी,

बैतूल। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना का लाभ लेने वाले 2745 हितग्राहियों में से करीब 24 हितग्राहियों ने आवास नहीं बनाये। इन हितग्राहियों ने आवास बनाने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं की, जबकि आगामी दिसंबर के बाद पीएम आवास निर्माण की समय सीमा खत्म हो जाएगी। ऐसे में नगरपालिका बैतूल द्वारा इन हितग्राहियों को नोटिस भेजकर राशि रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल पीएम आवास योजना के तहत बैतूल नपा द्वारा 2016 से लेकर 2022 तक कुल 2745 गरीबों का हितग्राही के रूप में चयन कर निर्माण के लिए पहली, दूसरी और तीसरी किस्त खातों में भेजी गई थी। भेजी गई राशि से हितग्राहियों को पीएम आवास का निर्माण करना था, जिसके बाद उन्हें अगली किस्त जारी होनी थी। लेकिन 24 हितग्राहियों द्वारा पीएम आवास की राशि लेने के बाद अभी तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया गया। बता दे कि नगरपालिका बैतूल अंतर्गत स्वीकृत 2745 आवासों में से 2696 आवास पूर्ण हो चुके है, जबकि 49 आवास अधूरे है। वहीं 10 से 12 लोग को अभी तीसरी राशि का इंतजार है।

नपा ने राशि वसूली के लिए प्रकरण बनाकर भेजे

जिन हितग्राहियों ने राशि लेने के बाद भी मकान का काम शुरू नहीं किया, ऐसे 24 लोगों से राशि वसूली के लिए नगरपालिका ने प्रकरण बनाकर भेज दिये है। हालांकि इनमें से 7 लोगों ने करीब 7 लाख 10 हजार

रुपये की राशि भी सरेंडर कर दी है, जबकि 17 लोगों से राशि वसूल की जानी है। वहीं एक हितग्राही ने खुद ही किन्हीं कारण से राशि सरेंडर कर दी। बताया गया कि आगामी दिसंबर तक सभी स्वीकृत पीएम आवास का निर्माण पूर्ण किया जाना है। समय सीमा समाप्त होने के बाद नपा आवास नहीं बनाने वाले लाभार्थियों से शासन की राशि वसूली की कार्रवाई शुरू करेगी।

राशि सरेंडर नहीं करने पर हो सकती है सख्त कार्यवाही

पीएम आवास योजना के दूसरे चरण को शुरू करने से पहले नपा को स्वीकृत आवासों की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करना है। बताया जा रहा है कि अपूर्ण निर्माण करने वालों या आवास नहीं बनाने वालों और राशि सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किये है। वहीं कुर्की की कार्रवाई भी कर सकती है। बताया गया कि पीएम आवास के पहले फेज में स्वीकृत आवास अधूरे हैं। ऐसे हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है और इस राशि की वसूली की जाएगी। पहले चरण में चयनित किए गए हितग्राहियों के बैंक खातों में पहली और दूसरी किस्त भेजी गई थी। लेकिन उनके द्वारा राशि आहरण करने के बाद भी आवास निर्माण नहीं किया।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में 231 आवास स्वीकृत

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में नगरपालिका द्वारा पांच बार आवासों की डीपीआर बनाकर शासन को भेजी, जिसके बाद नगरपालिका बैतूल क्षेत्र अंतर्गत 231 मकान स्वीकृत हुए है। वहीं 6वीं डीपीआर में 31 मकानों के स्वीकृत होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में कुल 551 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 92 आवेदन दस्तावेजों की कमी सहित अन्य कारणों से रिजेक्ट हो गये है, वहीं 93 लोगों ने आवेदन वापस ले लिये है। इसके अलावा 99 आवेदन पेडिंग है।

इनका कहना है -

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लोगों ने राशि सरेंडर कर दी है, वहीं जिन हितग्राहियों ने आवास नहीं बनाये है या काम ही शुरू नहीं किया है, ऐसे हितग्राहियों से राशि वसूली के लिए नोटिस जारी किये है और उनके प्रकरण बनाकर भेजे गये है।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नपा बैतूल

एग्रोविजन कृषि मेले में कृषि विभाग बैतूल की सहभागिता

बैतूल। एग्रोविजन का 16 वां संस्करण 21 नवंबर से नागपुर में प्रारंभ हुआ है, जो 24 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। उक्त मेले में मध्यप्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा तथा सिवनी जिले के द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। मेले में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कृषकों के जैविक, मिलेट उत्पाद के लिए प्रमुख मंच के रूप में, एग्रोविज़न 2025 किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। एग्रोविजन मेले में कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक, उन्नत कृषि मशीनरी, मत्स्य, रेशम, पशुपालन की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो रही है। मेले में कृषकों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी, मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

उप संचालक कृषि डॉ आनंद कुमार बडोनिया ने बताया कि एग्रोविजन मेला में देश-विदेश के कृषि तथा कृषि से संबंधित कृषक एवं उद्योगपति उपस्थित होने से जिले के कृषकों के उत्पाद को मंच प्राप्त हो रहा है। मेले के शुभारंभ दिवस पर स्टाल प्रदर्शनी में बैतूल जिले के विकासखंड आमला के कृषक श्री लोकेश गावंडे के केंचुआ खाद, कोसमी बैतूल के कच्ची घानी से शुद्ध तेल निर्माता श्री महेन्द्र श्रीराम पिंपलकर के मूंगफली तेल, पाढर के कृषक श्री सुरेन्द्र धुर्वे के उत्पाद काले चावल, सतपुडांचल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शाहपुर के मिलेट से बने उत्पाद जैसे ज्वार बिस्किट, रागी बिस्कुट, तुरंत तैयार होने वाले डोसा, उपमा, पास्ता, सावा, रागी तथा बैतूल जिले की पहचान गड़मल ''एक स्थानीय और दुर्लभ दलहनी (पल्स) फसल'' (मुख्य रूप से भीमपुर विकासखंड के दामजीपुरा गांव और आस-पास के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उगाई जाती है) आदि को प्रदर्शनी स्टॉल में रखा गया है। एग्रोविजन मेले में बैतूल के कृषकों के उत्पाद को सराहना मिल रही है तथा उत्पादक कृषकों को मांग एवं ब्रांड के लिए एक उपयोगी आधार प्राप्त हो रहा है। मेले के नोडल अधिकारी सुरेंद्र परहाते, कमलेश मस्की, मनीष सोडगे आदी मेले में उपस्थित रहे।

ट्रैक्टर की चपेट में आया 7 वर्षीय बालक, मौत

बैतूल। बैतूल गंज थाना क्षेत्र के खेड़ला किला गांव में बुधवार को खेत में खेल रहे 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। वह खेत में चल रहे ट्रैक्टर के पास खेल रहा था। इसी दौरान दौड़ते हुए ट्रैक्टर के बड़े टायर की चपेट में आ गया। बच्चे को नाना तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है। डॉक्टरों के अनुसार मोहित के कान और नाक से खून निकल रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई थी। अस्पताल पुलिस चौकी ने मोहित का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

टिकारी-गड़ाघाट रोड निर्माण का भूमिपूजन 22 नवंबर को

बैतूल। 2.70 किलोमीटर लंबे टिकारी-गाड़ाघाट सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन शनिवार को अखाड़ा चौक टिकारी में प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण पर लगभग 789.35 लाख रुपए की लागत आएगी। बैतूल स्टेशन मार्ग के नाम से बनने वाली यह रोड यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके, प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल, सुधाकर पवार, आदित्य बबला शुक्ला, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वतीबाई बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर तथा पार्षद श्रीमती वर्षा बारस्कर, रजनी वर्मा और सुभाष लोखंडे की उपस्थिति रहेगी।

29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में बैतूल जिले से चयनित प्रतिभागियों का एसपी ने किया उत्साहवर्धन

बैतूल। मध्य प्रदेश शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रदेशभर के युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु आयोजित 29वां युवा महोत्सव 17 एवं 18 नवंबर 2025 को भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में संपन्न हुआ। उक्त राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नर्मदापुरम संभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला बैतूल के प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित कीं। जिला बैतूल की प्रतिभावान छात्रा प्रतिष्ठा सिंह ठाकुर को उनके विज्ञान मॉडल पोर्टेबल पावर स्टेशन एवं आपदा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान तथा वैशाली नरवरे को कविता लेखन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन द्वारा राज्य स्तर पर चयनित इन प्रतिभागियों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया गया। इस दौरान प्रतिष्ठा सिंह ठाकुर ने अपने विज्ञान मॉडल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षक नीतिश भार्गव ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि उनके मार्गदर्शन में जिले के बच्चों के मॉडल प्रदेश स्तर पर चयनित हुए हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने दोनों छात्राओं सहित समस्त प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिला बैतूल की प्रतिभाओं को राज्य स्तर पर पहचान मिलना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। खेल, कला, साहित्य और विज्ञान से जुड़ी गतिविधियाँ न केवल व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करती हैं। छात्रों को उच्च स्तर पर बेहतर प्रदर्शन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि खेल एवं रचनात्मक गतिविधियाँ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और युवा पीढ़ी को इन क्षेत्रों में आगे बढने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इस अवसर पर जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील, प्रशिक्षक तपेश साहू, युवा समन्वयक रामनारायण शुक्ला, मनीष शर्मा एवं शिक्षक नीतिश भार्गव उपस्थित रहे।

शाहपुर में कांग्रेस बीएलए को मिला विशेष एसआईआर प्रशिक्षण

बैतूल। शाहपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एसआईआर जानकारी संबंधित प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के बीएलए को

एसआईआर से संबंधित सभी आवश्यक जानकारिया प्रशिक्षण प्रभारी स्पेंसर लाल और मोनू वाघ द्वारा विस्तार से प्रदान की गई। शिविर में पार्टी नेतृत्व की मजबूत उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से 2023 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राहुल उइके, पूर्व विधायक ब्रम्हा भलावी, भौंरा उपखंड अध्यक्ष शिवकुमार मालवीय, पहलवान सिंह ठाकुर, धर्मेंद्र शुक्ला, ओम कवडकर, रिंकू वर्मा, विवेक ठाकुर, आयुष शुक्ला, युवक कांग्रेस शाहपुर के अध्यक्ष पिंटू वरकड़े, नवनियुक्त जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष कमलेश यादव, अमित तिवारी, सिद्दीक कुरैशी, दिनेश यादव, धीरज यादव, परसराम आह्राके, रेखा टेकाम, सरोज परते सहित बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

यूनिटी मार्च में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एवं जनप्रतिनिधि

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर सारणी में निकला भव्य यूनिटी मार्च

बैतूल। सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर देशभर में आयोजित किए जा रहे यूनिटी मार्च के अंतर्गत शुक्रवार को वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सरदार विष्णु सिंह उईके महाविद्यालय, सारणी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री दुर्गादास उईके, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे, विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके, जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर, सुधाकर पवार, नगर पालिका अध्यक्ष सारणी किशोर बर्दे, जिला युवा अधिकारी सुषमा गवली, प्राचार्य प्रदीप पेंद्राम सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कमलेश सिंह ने किया।

सुधाकर पवार ने सभी को एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार विष्णु सिंह उईके की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण से हुई। इसके उपरांत वंदेमातरम् के सामूहिक गायन के साथ कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उईके ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद जिन कठिन परिस्थितियों में सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा, वह इतिहास का अद्भुत अध्याय है। युवा पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है।

उन्होंने युवाओं का आव्हान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मादा के 2047 तक विकासित भारत के सकल्प म युवा अग्रदूत बनें।

विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे ने कहा कि भारत अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम है। इतनी विविधताओं के बावजूद सरदार पटेल ने अपने अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता से भारत को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने सभी नागरिकों से सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने और एकता-अखंडता को मजबूत करने का आग्रह किया। जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष मोहन नागर ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक महान व्यक्तियों ने बलिदान दिया है। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के साथ-साथ आज़ाद भारत को एकजुट करने का कार्य दृढ़ इच्छाशक्ति से किया। अंग्रेजों की विभाजन नीति का विरोध कर उन्होंने राष्ट्र की एकता को अक्षुण्ण रखा।

स्कूली बच्चों व सामाजिक संगठनों की उत्साहपूर्ण भागीदारी..

यूनिटी मार्च में स्कूली बच्चों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सरदार विष्णु सिंह उईके महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत लोकनृत्य ने सभी को मंत्रमुग्ध किया, जबकि डीपीएस स्कूल सारणी के विद्यार्थियों ने सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर आधारित नृत्य से उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। इसके बाद अतिथियों, नागरिकों और सभी प्रतिभागियों ने तिरंगा थामे जोश और उमंग के साथ यूनिटी मार्च निकाला।

यह यूनिटी मार्च का आयोजन बागडोना से पाथाखेड़ा तक किया गया। भारत माता की जय, सरदार वल्लभभाई पटेल अमर रहें, वंदे मातरम के नारों से नगर गूंज उठा।

पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री विभंजनसागर मुनिराज का धार चातुर्मास करने के बाद कागदीपुरा की और मंगल विहार

ग्राम अनारद में संत भवन का लोकार्पण मुनिश्री के सानिध्य में संपन्न

धार। दिगंबर जैन समाज में चातुर्मास सम्पन्न होने के बाद पूज्य मुनिश्री उपाध्याय श्री विभंजनसागर का ससंघ कागदीपुरा तीर्थ की ओर विहार हुआ। पूज्य मुनि श्री अपने आहु पार्श्वनाथ एवं ग्राम अनारद के प्रवास पर थे। पूज्य मुनि श्री के पावन सानिध्य में अनारद में संत सदन का लोकार्पण किया गया। पश्चात वापस धार होते हुए कागदीपुरा तीर्थ की ओर विहार हुआ। समाज के सभी सदस्यो ने भावभीनी नम आँखों से पूज्य मुनि श्री का विहार करवाया। मुनिश्री के चरणो में पुनः धार नगर में पधारने के लिये निवेदन किया। पूज्य मुनिश्री का चातुर्मास सफ़ल बनाने के लिए अध्यक्ष श्रेणिक गंगवाल ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। जानकारी मीडिया प्रभारी संजय गंगवाल ने दी।

यातायात नियमों को लेकर जन-जागरुकता अभियान चलाया गया

धार। जिले में यातायात दुर्घटना में मृत्यु दर प्रदेश में सर्वाधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए संस्था विचरती, जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से विद्यालयों में जन जागरूकता अभियान प्रारंभ धार के माडल स्कूल से प्रारंभ किया गया था। उसी अभियान को आज आगे बढ़ाते हुये शासकीय आई टी आई कालेज में बच्चों से रुबरु होकर यातायात थाना प्रभारी प्रेमसिंह ठाकुर ने यातायात

के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ ही वाहन लायसेंस को लेकर जागरुक किया साथ ही मुस्कान योजना के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर संस्था विचरती की और से वक्ता अमित मांडलिक ने नशे से बचने और अपना भविष्य सुरक्षित रखने का आग्रह किया । संस्था अध्यक्ष श्याम नायक ने युवाओं को यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रवीण सवनेर ने किया। इस अवसर पर संस्था के कपिल अलावा, ऋषि मालवीय , सुमित ओसारी, योगेश अलावा, बादल जैन, रुद्राक्ष गुप्ता धीरज भाटी, सागर ठाकुर, वीरेन्द्र चौहान,उपस्थित रहे । आभार आई टी आई स्कूल के उप प्राचार्य सर ने किया। जानकारी संस्था के सचिव रोहित पंवार ने दी।

एसआईआर अभियान की प्रगति को जानने कलेक्टर का औचक निरीक्षण, धार शहर में किया भ्रमण

धार । कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने शुक्रवार को धार शहरी क्षेत्र का भ्रमण कर स्पेशल समरी रिवीजन (#SIR) से जुड़े कार्यों का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और चल रहे कार्यों में और अधिक गति लाने पर जोर दिया। भ्रमण के बाद कलेक्टर मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीएलओ के साथ ही सभी एसडीएम और तहसीलदारों से विस्तृत चर्चा करते हुए अभियान की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर अभियान में शत प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने वाले बीएलओ को आगामी टीएल बैठक में प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने जिला स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित होने की जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने क्षेत्र में निरंतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से उनके कार्य, प्रगति, समय-सीमा और उन क्षेत्रों के बारे में पूछताछ की जहाँ और अधिक ध्यान

दिए जाने की आवश्यकता है।

कलेक्टर ने बीएलओ से काम की कठिनाइयों को समझा और उनके समाधान भी बताए। साथ ही बीएलए से मिलने वाले सहयोग के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आवश्यक हो तो क्षेत्रों में मुनादी कराई जाए ताकि अधिक से अधिक मतदाता अद्यतन प्रक्रिया से जुड़ सकें।

उन्होंने अपील की कि जो भी मतदाता कार्यस्थलों पर जाते हैं, उनसे आग्रह किया जाए कि मात्र दस मिनट निकालकर अपने फॉर्म भरें, जिससे अभियान की प्रगति तेज़ी से सुनिश्चित की जा सके। कलेक्टर ने दोहराया कि जिला स्तर पर लगाए गए अधिकारी एसआईआर अभियान की सतत मॉनिटरिंग करें, ताकि सभी निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे हो सकें।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर चार प्राथमिक शिक्षक निलंबित

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले चार प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आदेश सहायक आयुक्त नरोत्तम वरकड़े द्वारा जारी किए गए।निर्वाचन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में उदासीनता और कर्तव्य में लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिन शिक्षकों को निलंबित किया गया है, उनमें सुनील दुबे, प्राथमिक शिक्षक, प्रा.वि. सुलीबर्डी विकासखंड नालछा; सीताराम डावर, प्राथमिक शिक्षक, प्रा.वि. नागझिरी विकासखंड नालछा; मुकेश रावत, प्राथमिक शिक्षक, प्रा.वि. बयडीपुरा डेडगांव विकासखंड उमरबन; और मालसिंह चौहान, प्राथमिक शिक्षक, प्रा.वि. नाकेदारपुरा विकासखंड उमरबन शामिल हैं।

वर्षों बाद अपनी जमा धनराशि प्राप्त कर ग्राहकों ने महसूस की राहत

आरबीआई व एसएलबीसी भोपाल के निर्देश पर लीड बैंक में राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू
आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान के तहत दावा सुविधा शिविर आयोजित

बैतूल। भारतीय रिजर्व बैंक एवं एसएलबीसी भोपाल के निर्देशानुसार लीड बैंक कार्यालय बैतूल द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान आपकी पूंजी, आपका अधिकार के अंतर्गत जिला स्तरीय दावा सुविधा एवं आउटरीच शिविर का आयोजन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोठीबाजार शाखा परिसर में शुक्रवार 21 नवंबर को किया गया। यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक तीन माह तक चलाया जा रहा है।

शिविर के दौरान खाताधारकों के दावों का निपटारा किया गया तथा उपभोक्ता अधिकारों और बैंकिंग जागरूकता से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। विशेष रूप से उन ग्राहकों को आमंत्रित किया गया, जिनके बैंक खाते 10 वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय थे। दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत इन खातों को पुनः सक्रिय किया गया और ग्राहकों को उनकी निष्क्रिय पड़ी राशि उपलब्ध कराई गई।

वर्षों बाद अपनी जमा धनराशि प्राप्त कर ग्राहकों ने राहत महसूस की। शिविर के दौरान अधिकारियों ने बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता व उपभोक्ता अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक देश के सभी जिलों में चलाया जा रहा है। शिविर को सफल बनाने हेतु व्यापक प्रचार किया गया। इस शिविर की सफलता ने न केवल नागरिकों का विश्वास बढ़ाया, बल्कि वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुआ। शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक के एलडीओ सौम्य चटर्जी, एलडीएम आशुतोष कुमार सिंह, जिला सहकारी बैंक की जीएम श्रीमती नीता निगम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोठी बाजार के मुख्य प्रबंधक राजीव रंजन झा सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक, शाखा प्रबंधक और बीमा कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह राष्ट्रव्यापी अभियान बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए। आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान के अंतर्गत आयोजित यह शिविर वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है, जिससे नागरिकों का बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा और अधिक सुदृढ़ हुआ।

डिजिटलाइजेशन कार्य में प्रथम आने पर बरसाली के बीएलओ का किया सम्मान

बैतूल। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत बैतूल विधानसभा क्षेत्र 131 में बीएलओ सुपरवाइजर तुलसीराम उईके के निर्देशन में कार्यरत मतदान केंद्र क्रमांक

150 बरसाली के बीएलओ बारीकराव सरियाम शिक्षक ने गणना पत्रकों के डिजिटलीकरण कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

इस उपलब्धि पर शुक्रवार को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह ने उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पुष्पगुच्छ और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रोत्साहन स्वरूप परिवार सहित फ्री मूवी टिकट एवं निःशुल्क रात्रि भोज का पुरस्कार भी प्रदान किया गया।

अपेक्षाकृत प्रगति प्राप्त करने के लिए सघन मॉनिटरिंग करें अधिकारी हर घंटे की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर सुनिश्चित करें समयबद्ध कार्य

एसआईआर प्रक्रिया किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी : कलेक्टर

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत की जा रही गतिविधियों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों में मतगणना प्रपत्रों के वितरण के पश्चात किए जा रहे डिजिटाइजेशन कार्य का गहनता से परीक्षण किया। कलेक्टर ने समस्त बीएलओ द्वारा अब तक किए जा चुके डिजिटाइजेशन के आंकड़ों की समीक्षा के आधार पर विधानसभा क्षेत्र होशंगाबाद की सबसे न्यून प्रगति पर गहन असंतोष व्यक्त करते हुए होशंगाबाद इआरओ/एसडीएम को निर्देश दिए की जिले की समग्र प्रगति में होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की भी यथेष्ठ सहभागिता सुनिश्चित करे।

उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान प्रगति अपेक्षाकृत नहीं है जिसकी गहनता से समीक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने एसडीएम नर्मदापुरम को निर्देश दिए की जिन मतदान केंद्र पर बीएलओ द्वारा लापरवाही की जा रही है उन केंद्रों पर बीएलओ के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित कर उनके स्थान पर रिजर्व बीएलओ से कार्य करवाया जाए। कलेक्टर ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किया जा रहे हैं किसी भी कार्य में लापरवाही स्वीकार्य नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बीएलओ की क्षमता निर्माण और प्रबंधन के कारण डिजिटाइजेशन की प्रगति कम है। उन्होंने निर्देश दिए की बीएलओ से लेकर सुपरवाइजर तक प्रत्येक स्तर पर सघन मॉनिटरिंग की अत्यंत आवश्यकता गई। कलेक्टर ने एसडीएम नर्मदापुरम को निर्देश दिए की सिटी मजिस्ट्रेट, तथा एसडीएम इटारसी के साथ संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित कर आगामी एक दिवस में अपेक्षाकृत प्रगति दर्ज करें। इस दौरान कलेक्टर ने अन्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अब तक हुई कार्यवाही की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए की नगरी निकाय द्वारा सहयोग नहीं दिए जाने की किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो यह सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नगर पालिका अमले के किसी बीएलओ द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कार्य नहीं किए जाने पर नियमनुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन बीएलओ द्वारा शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन किया जा चुका है उनसे चर्चा कर उनके द्वारा अपनाई गई रणनीति का भी विश्लेषण करें। उन्होंने धीमी प्रगति वाले मतदान केंद्रों पर मॉनिटरिंग की कमी पर कड़ा असंतोष जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर सुश्री मीना ने यह निर्देश भी दिए कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी के साथ भी सतत संपर्क बनाए रखें तथा उन्हें प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। कलेक्टर ने कहा कि मेप्ड डाटा का डिजिटाइजेशन पर सभी विशेष फोकस करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नियमित रूप से प्रत्येक घंटे की रिपोर्ट की समीक्षा कर अपेक्षित प्रगति दर्ज न होने की स्थिति में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजीव रंजन पांडे, एनएलएमटी श्री पंकज दुबे, निर्वाचन सुपरवाइजर श्री कैलाश दुबे सहित समस्त एसडीएम तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संभागायुक्त तथा आईजी ने सांची महोत्सव तथा मेला आयोजन की व्यवस्थाओं के संबंध में ली बैठक

रायसेन (निप्र)। जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची में 29 तथा 30 नवम्बर 2025 को महाबोधि महोत्सव एवं मेला का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को भोपाल संभागायुक्त श्री संजीव सिंह तथा आईजी श्री मिथलेश कुमार शुक्ला द्वारा सांची में आयोजित बैठक में महाबोधि महोत्सव तथा मेला आयोजन की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर डीआईजी श्री प्रशांत खरे भी उपस्थित रहे। प्रभारी कलेक्टर श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पाण्डे ने महाबोधि महोत्सव एवं मेला आयोजन के संबंध में अभी तक की गई व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। बैठक में संभागायुक्त श्री सिंह तथा आईजी श्री शुक्ला ने आयोजन के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था, वाहन पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए दिशा-निर्देश दिए। बैठक के उपरांत उन्होंने अधिकारियों के साथ बौद्ध स्तूप परिसर पहुंचकर भी व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, एएसपी श्री कमलेश कुमार, एसडीएम श्री मनीष शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ने से खुश हैं लाड़ली बहनें

रायसेन (निप्र)। प्रदेश की लाड़ली बहनों के हित में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की राशि को 1250 रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इससे प्रदेश की लाड़ली बहनें बेहद खुश हैं तथा स्वयं को और अधिक सशक्त तथा आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। रायसेन निवासी श्रीमती ऊषा नामदेव, कमला बाई, सीमा कुशवाह सहित अन्य लाड़ली बहनें मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि 1500 रूपए प्रतिमाह करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहती हैं कि यह योजना वास्तव में महिलाओं को सशक्त बना रही है तथा मुख्यमंत्री द्वारा राशि बढ़ाने से यह सहयोग और भी प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने वाली राशि उनके जीवन में बहुत मददगार साबित हो रही है, इससे उन्हें आत्मनिर्भरता मिली है। इस राशि का उपयोग वह परिवार की जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं तथा कुछ राशि की बचत भी कर रही है। उन्हें नवम्बर महीने में 1500 रूपए प्राप्त हुए हैं तथा आगे भी हर महीने 1500 रूपए मिलने से उनकी बचत में भी वृद्धि होगी।

नशा मुक्त भारत अभियान के 05 वर्ष पूर्ण होने पर नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सीहोर (निप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर आष्टा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देवास सांसद श्री महेंद्र सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा, आष्टा विधायक श्री गोपाल सिंह इंजीनियर सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर पंजाब के अमृतसर में आयोजित राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों विशेषकर युवाओं और छात्र-छात्राओं को नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों से अवगत कराना और नशामुक्ति के लिए प्रेरित करना है। इसके साथ ही अभियान में सामुदायिक भागीदारी को बढाना और नशा मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों को मजबूत करना है। इस अवसर पर सभी को नशामुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती हेंमकुंवर रायसिंह मेवाड़ा, एसडीएम श्री नितिन टाले, उपसंचालक श्री महेश यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, युवा उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने बासौदा में एसआईआर कार्यों की समीक्षा की

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज बासौदा के पटवारी सभागार में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित राजस्व टीम से मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की जानकारी ली और प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बीएलओ के द्वारा मतदाता से संबंधित जानकारी आयोग के निर्धारित एन्युमेरेशन फार्म में प्राप्ति के उपरांत बीएलओ एप के माध्यम से दर्ज करने के कार्यों का मुआयना किया है। उन्होंने एसआईआर कार्य को अति महत्वपूर्ण बताते हुए समय सीमा में मतदाता सूची में शुद्धता संबंधी सभी प्रविष्टियों के निराकरण करने की बात कही है। उन्होंने बीएलओ द्वारा किए जा रहे मैदानी कार्यों की बारीकी से जांच करने के निर्देश मौके पर दिए हैं।। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने, त्रुटिरहित प्रविष्टियां सुनिश्चित करने और प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करने के कार्यों में कहीं त्रुटि ना हो पाए के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती की नींव हैं, इसलिए इन्हें गंभीरता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने इससे पहले बासौदा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और संधारित विभिन्न पंजियों का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री संतोष बिटौलिया, तहसीलदार सुश्री रितु राय भी मौजूद रही।

जिला लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक आयोजित

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में बुधवार को जिला लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के उद्यमियों की प्रदूषण बोर्ड, बिजली विभाग, नगर पालिका एवं अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं के निराकरण पर विचार विमर्श किया गया।

एसआईआर के तहत खरतलाब बना पहला 100 प्रतिशत सर्वेक्षण पूर्ण करने वाला ग्राम

कलेक्टर ने बीएलओ श्री दिलारे को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित

हरदा (निप्र)। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत हरदा जिले की विधानसभा टिमरनी के मतदान केन्द्र क्रमांक 68 खरतलाब में नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर श्री हंसकुमार दिलारे द्वारा 17 नवम्बर की शाम तक समस्त कार्य शतप्रतिशत पूर्ण किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को श्री बीएलओ श्री दिलारे को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पुरूषोत्तम कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बूथ लेवल ऑफिसर श्री दिलारे ने बताया कि इस कार्य को पूर्ण करने में उनके द्वारा नियमित तीन प्रशिक्षण प्राप्त किये गये। साथ ही सहयोग के लिये एक सहायक अधिकारी भी उनके साथ नियुक्त था। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई मतदाता सूची को लेकर उन्होने गांव का घर-घर भ्रमण किया एवं बाहर से आये मतदाताओं की जानकारी प्राप्त की। जो मतदाता अथवा नव विवाहिता अन्य स्थानों से ग्राम में आये थे, उनकी जानकारी पोर्टल पर लिंक के माध्यम से प्राप्त की, जिससे सर्वेक्षण कार्य में सरलता हुई। ग्रामीणों द्वारा भी एसआईआर से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग किया गया, जिसके चलते तत्परता से यह कार्य पूर्ण हुआ। ग्राम चिड़गांव मतदान केन्द्र पर भी 83.64 कार्य पूर्ण हुआ इसी प्रकार हरदा विधानसभा अंतर्गत मतदान क्रमांक मतदान केंद्र क्रमांक 28 चिड़गांव के बीएलओ श्री लोकेश बिश्नोई ने सोमवार 17 नवम्बर की शाम तक 83.64 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। सोमवार 17 नवम्बर की शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस कार्य की सराहना की गई। साथ ही कहा गया कि जो बीएलओ तत्परता से शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करेंगे उनको 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस कार्य में जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी तत्परता से शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करेंगे वह भी सम्मानित होंगे। उल्लेखनीय है कि जिले में कम मतदाता संख्या वाले मतदान केन्द्रों पर एसआईआर का कार्य पहले शुरू किया गया है ताकि इन मतदान केंद्रों का शत-प्रतिशत एसआईआर का शीघ्र कार्य किया जाकर आगे कार्य संपन्न किया जा सके।

षड्यंत्र पूर्वक पद का दुरूप्रयोग कर भ्रष्टाचार करने वाले आरोपीगण को हुई सजा

भोपाल। विशेष लोक अभियोजक श्रीमती हेमलता कुशवाह ने बताया कि आज दिनांक 21/11/2025 माननीय विशेष न्यायालय श्री मनोज कुमार सिंह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के द्वारा जिला सहकारी एवं ग्रामीण विकास बैंक के अधिकारीगण जिनमे विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, आर एस गर्ग, पुष्टीकर्ता अधिकारी, हुकुमचन्द सिंघाई महाप्रबधंक एवं क्रेता राजेन्द्र प्रसाद पाटीदार को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये, विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, आर एस गर्ग, पुष्टीकर्ता अधिकारी, हुकुमचन्द सिंघाई महाप्रबधंक एवं क्रेता राजेन्द्र प्रसाद पाटीदार को धारा 420 सहपठित धारा 120-बी भादवि मे 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000-1000 अर्थदण्ड (प्रत्येक आरोपी को) एवं आरोपीगण विक्रय अधिकारी हरिहर प्रसाद मिश्रा, आर एस गर्ग, पुष्टीकर्ता अधिकारी, हुकुमचन्द सिंघाई महाप्रबधंक को धारा 13-1(डी) सहपठित 13(2) पीसी एक्ट में प्रत्येक धारा मे 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड, (प्रत्येक आरोपी को) से दण्डित का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाहा द्वारा पैरवी की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

ग्राम बरई तहसील हुजूर जिला भोपाल के कृषक आदिवासी नारायण सिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि 1989 मे बंधक रख 18,000 रू का लोन पंप एवं थ्रसर के लिये लिया था आरोपीगण द्वारा कृषक की 4.50 एकड़ भूमि दिनांक 29/03/2000 को 1 लाख 10 हजार रूपये मे राजेन्द्र प्रसाद को नीलामी प्रक्रिया का उल्लंघन कर कृषि भूमि बाजार मूल्य एवं कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य से अत्याधिक कम मूल्यो पर अवैधानिक रूप से नियम के विरूद्ध नीलामी कार्यवाही कर धोखाधाड़ी कर अपने पद का दुरूप्रयोग करते हुए नीलामी संबंधित नोटशीट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पुष्टि हेतु संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ भोपाल को भेजा गया, जहां उनके द्वारा अवैधानिक रूप से नीलामी की पुष्टि आदेश पारित किया गया। उक्त लिखित सूचना के आधार पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच कर अपराध पंजीबद्ध किया गया विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य, दस्तोवजों, लिखित तर्को से सहमत होते हुये आरोपीगण उक्त धाराओं से दण्डित किया गया।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत दिलाई शपथ

हरदा (निप्र)। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत तंबाकू मुक्त युवा अभियान के लिए बुधवार को महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को तम्बाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान शासकीय स्वामी विवेकानंद कॉलेज एवं पालीटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं को जिला नोडल अधिकारी डॉ. पीयूष दोगने एवं डॉ आयुषी गुप्ता ने तम्बाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य श्रीमती संगीता बिले के साथ सभी शिक्षक भी उपस्थित रहे। हरदा डिग्री कॉलेज हरदा में मास्टर ट्रेनर नशा मुक्त भारत अभियान नीरज गुर्जर द्वारा छब्ब् कैडेट्स को शपथ दिलवाई गई तथा समाज में नशा मुक्त बनाने हेतु जागरूकता अभियान चलाने की अपील की गई।

कलेक्टर ने एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण कर दिए कार्य में तेजी लाने का निर्देश

तेजी से कार्य के लिए बीएलओ को किया प्रोत्साहित

एसआईआर प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें लापरवाही न बरती जाए : कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को समयबद्ध और प्रभावी रूप से पूर्ण कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बालागुरू के. ने ग्राम बिलकिसगंज, बरखेड़ी, पिपलिया मीरा, बिजलोन और खेड़ली सहित कई मतदान केंद्रों पर चल रही एसआईआर प्रक्रिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर किए जा रहे गणना पत्रक वितरण, संकलन तथा बीएलओ ऐप पर अपलोड की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी बीएलओ से चर्चा कर प्रगति की जानकारी ली और उन्हें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीएलओ से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए फॉर्म भरने से लेकर डिजिटलीकरण तक किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने उन क्षेत्रों में भी वास्तविक स्थिति देखी आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर अनुपास्थित बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देने के लिए कहा। उन्होंने कहा सभी बीएलओ एवं संबंधित अधिकारी समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित हों और एसआईआर कार्य को प्राथमिकता दें। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिले की एसआईआर प्रगति लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन इसे और तेज करने की आवश्यकता है ताकि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जा सके। उन्होंने बीएलओ को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जिले के कई बीएलओ अपने उत्कृष्ट कार्य के कारण राज्य स्तर पर सम्मानित हुए हैं, जो अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निरीक्षण के दौरान स्थानीय अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि एसआईआर कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या, फॉर्म उपलब्धता, अपलोडिंग या सत्यापन कार्य में बीएलओ को हर संभव सहायता शीघ्रता से उपलब्ध कराई जाए, ताकि कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

18 बीएलओ ने मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन का सराहनीय कार्य किया

विदिशा (निप्र)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 फिर का कार्यक्रम जारी है जिसके अंतर्गत विदिशा जिले के बीएलओ द्वारा मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन का कार्य सराहनीय रहा है। बीएलओ द्वारा मतदाताओं के गणना फॉर्म का डिजिटाइजेशन के सराहनीय कार्य में उपलब्धि परिलक्षित करते हुए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 148 शमशाबाद के मतदान केंद्र क्रमांक 139 के बीएलओ श्री वीरेंद्र सिंह यादव ने 79.02 प्रतिशत गणना फॉर्मों का डिजिटाइजेशन का कार्य किया है। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 144 विदिशा के मतदान केंद्र क्रमांक 12 के बीएलओ श्री मनोज कुमार साहू द्वारा 77.29 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 273 के बीएलओ श्री दिनेश कुमार अहिरवार ने 68.02 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 65 की बीएलओ श्रीमती अर्चना त्रिपाठी ने 65.63 प्रतिशत, मतदान क्रमांक 01 के बीएलओ श्री कमलेश कुमार सक्सेना ने 64.64 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 47 की बीएलओ श्रीमती मरियम कुल्लू ने 62.45 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 247 के बीएलओ श्री नवीन शर्मा ने 60.16 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 45 के बीएलओ श्री नरेंद्र रघुवंशी ने 59.74 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 11 की बीएलओ श्रीमती कल्पना राजपूत ने 59.08 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 46 की बीएलओ सुशीला भास्कर ने 58.23 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 272 के बीएलओ श्री सुभाष चंद्र मीणा ने 57.21 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 18 के बीएलओ श्री हरि सिंह रघुवंशी ने 52.99 प्रतिशत के अलावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 145 बासौदा के मतदान केंद्र क्रमांक 80 के बीएलओ शशि शर्मा ने 64.86 प्रतिशत, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 146 कुरवाई के मतदान केंद्र क्रमांक 140 के बीएलओ श्री धर्मेंद्र रघुवंशी ने 76.18 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 199 के बीएलओ श्री राजेश कुर्मी ने 54.78 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 110 के बीएलओ श्री वकील सिंह ने 54.76 प्रतिशत, मतदान केंद्र क्रमांक 70 के बीएलओ श्री कमलेश बैरागी ने 51.26 प्रतिशत और मतदान केंद्र क्रमांक 72 के बीएलओ श्री जसवंत सिंह बघेल ने 50.26 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। विदिशा जिला अंतर्गत 125836 मतदाताओं के गणना फॉर्मों का डिजिटाइजेशन किया गया है।

घरेलू हिंसा क्या महिला पुलिस के साथ भी होती है..एक छात्रा ने सूबेदार मेघा शर्मा से पूछा...

विदिशा (निप्र)। पुलिस सेवा लड़कियों को आत्मनिर्भर, साहसी और नेतृत्व-क्षमता से सम्पन्न बनाती है। कठोर प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। सरकारी नौकरी होने के कारण इसमें सुरक्षा, सम्मान, स्थिर आय और करियर वृद्धि जैसे अवसर भी उपलब्ध होते हैं, जो महिलाओं के लिए एक मजबूत भविष्य सुनिश्चित करते हैं। लड़कियों का पुलिस बनना न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि समाज के सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। यह बात सूबेदार मेघा शर्मा ने कही। शासकीय आदर्श महाविद्यालय विदिशा में आयोजित छह दिवसीय कार्यशाला के तीसरे दिन छात्राओं ने मेघा शर्मा से उनके जीवन और भविष्य में आने वाली चुनौतियों को लेकर भी कई सवाल किए। इस मौके पर सूबेदार भागीरथ प्रसाद ने कहा की लड़कियों का पुलिस बनना न केवल व्यक्तिगत सफलता बल्कि समाज के सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉ.ब्रह्मदीप अलूने ने की वहीं संचालन डॉ अनीता शाक्य ने किया। विशेष व्याख्यान हिंदी पर डॉ स्मिता सिंघई ने किया। 22 नवम्बर तक चलने वाली कार्यशाला के चैथे दिन गुरुवार को सूबेदार आशीष रॉय विद्यार्थियों के बीच होंगे। वहीं सामान्य विज्ञान पर डॉ अनीता शाक्य और डॉ सुषमा सिसोदिया का विशेष व्याख्यान होगा।

सूबेदार मेघा शर्मा से विद्यार्थियों ने किए दिलचस्प सवाल

छात्रा-सलोनी खंगार

प्रश्न- रात को महिला पुलिस को ड्यूटी करने में क्या क्या समस्याएं सामने आती है..।

उत्तर-कानून और व्यवस्था बनाएं रखना पुलिस का काम है और पुलिस इसे मुस्तैदी से करती है। महिला पुलिस के लिए रात को ड्यूटी करना वैसे ही है,जैसे कोई पुरुष। महिला सुरक्षा को लेकर कानून सख्त किए गए है,जिसका खौफ अपराधियों पर भी रहता है । विभाग का समन्वय भी बेहतर होता है। इसलिए आमतौर पर ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं आती।

छात्रा-मनीषा अहिरवार: प्रश्न- घरेलू हिंसा क्या महिला पुलिस के साथ भी होती है..।

उत्तर - बिल्कुल हो सकती है । हिंसा का संबंध किसी पद से नहीं होता बल्कि आदतों और मस्तिष्क से होता है । घरेलू हिंसा की संभावना उन महिलाओं के साथ ज्यादा होती है जो पहली बार सह लेती है। एक बार महिला पर हाथ उठाने वाला पुरुष ऐसा बार बार करता है। किसी भी महिला को चाहिए की पहली बार ही उसका प्रतिकार कर दे,घरेलू हिंसा फिर कभी नहीं होंगी।

छात्रा-सुखदेव सेन : प्रश्न- महिला और पुरुष की पुलिसिंग में क्या अंतर है....।

उत्तर -पुलिसिंग,पुलिसिंग होती है इसका महिला या पुरुष होने से फर्क नहीं पड़ता। जो ड्यूटी के दौरान कार्य करना होता,सभी करते है। फिर भी पुरुष और महिला को लेकर सामाजिक मनोयोग थोडा अंतर पैदा कर सकता है। हिंसा से प्रभावित कोई भी महिला,महिला पुलिस के सामने अपनी बात को बेहतर तरीके से रखती है। वहीं बच्चों की महिला पुलिस से जुड़ने या भरोसा करने की सम्भावना ज्यादा बढ़ जाती है।

छात्रा-हर्षिता चैबे : प्रश्न- ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में पुलिसिंग करने में क्या अंतर है... ।

उत्तर - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्याओं में अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आमतौर पर भोले भाले होते है, एक दूसरे से परिचित होते है और वे पुलिस से सहज जुड़ जाते है। वहीं शहरी क्षेत्रों में ज्यादा चैकन्ना रहने की जरूरत होती है । भीड़ के बीच अनजान लोग और आवाजाही पर नजर रखना होती है।

छात्रा-नैनसी चैबे: प्रश्न - जब पुलिस में आपकी नौकरी लगी तो समाज का क्या नजरिया था।

उत्तर- मैं एक बहुत ही मध्यमवर्गीय परिवार से हूँ। पुलिस की तैयारी करते हुए पिताजी से यह बात साझा नहीं करती थी,माँ हमेशा प्रोत्साहित करती रही। लेकिन जब चयन हो गया तो अब पिताजी भी गर्व करते है। बेटियां अब पुलिस बनकर भी सफल हो रही है और अब माता पिता पुलिस या सेना में जाने के लिए बेटियों को प्रोत्साहित करने लगे है।

'पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा' का हुआ शुभारंभ

सांसद श्री पाटिल एवं विधायक श्री पटेल ने उज्जैन से ओंकारेश्वर पहुंचे यात्रियों का किया स्वागत

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने और पर्यटकों को त्वरित, सुगम और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर भोपाल से 'पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा' का शुभारंभ किया था। इसके तहत ओंकारेश्वर में शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से उज्जैन से 5 तीर्थ यात्रियों का आगमन खण्डवा के ग्राम कोठी के हेलीपैड पर हुआ। खंडवा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल और मांधाता विधायक श्री नारायण पटेल ने हेलीकॉप्टर से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से आए 5 तीर्थ यात्रियों ने ओंकारेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। 'पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा' के शुभारंभ अवसर पर सांसद श्री पाटिल ने कहा कि आज का दिन खंडवा जिले और ओंकारेश्वर के नागरिकों के लिए गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गत 11 वर्षों में उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंग को टूरिस्ट सर्किट और हवाई यात्रा सुविधा से जोड़ा गया है। इस सुविधा के

प्रारंभ होने से तीर्थ यात्री कम समय में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो यात्री समय के अभाव में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते थे, वे हेलीकॉप्टर सेवा से ओंकारेश्वर और उज्जैन आकर मध्यप्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में ओंकारेश्वर में विकास कार्य लगातार जारी हैं। ओंकारेश्वर में एकात्म धाम विकसित हो रहा है, नर्मदा किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार जारी है। सिंहस्थ-2028 प्रारंभ होने से पहले ओंकारेश्वर फोरलेन सड़क से तो जुड़ ही जाएगा, साथ ही ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन भी शीघ्र ही प्रारंभ होगा, जिससे रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। उन्होंने पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया।

विधायक श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हर समुदाय और हर वर्ग के लिए विकास योजनाएं प्रारंभ की हैं। ओंकारेश्वर अब हवाई मार्ग से भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि ओंकारेश्वर में हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए भविष्य में हेलीकॉप्टर सेवा के राउंड बढ़ाए जाएंगे, जिससे अधिक यात्री इस सुविधा का लाभ ले सकें। विधायक श्री पटेल ने कहा कि ओंकारेश्वर में विकास कार्यों के लगातार होने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे स्थानीय व्यवसायियों की आय भी बढ़ रही है।

अपर कलेक्टर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा ने इस अवसर पर बताया कि इस नई सुविधा से पर्यटकों को कम समय में अधिक गंतव्यों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. नरेशचंद्र सिंह की जयंती पर दी श्रद्धांजलि

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को म.प्र. विधानसभा भवन पहुंचकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री नरेशचंद्र सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्री नरेशचंद्र सिंह राज गोंड प्रदेश के इतिहास में एकमात्र जनजातीय और मध्यप्रदेश के 6वें मुख्यमंत्री रहे। उनकी कार्य अवधि 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक कुल 13 दिन रही। उनके मुख्यमंत्री बनने का समय संविद सरकार थी। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। इस अवसर पर विधायक श्री भगवान दास सबनानी, विधानसभा के प्रमुख सचिव सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर का हुआ सफल आयोजन

भोपाल (नप्र)। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के तहत ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा पेंशनर्स की सुविधा के लिए 20 नवंबर को भोपाल स्थित एम.पी. ट्रांसको के प्रशासनिक भवन, बिजली नगर, गोविंदपुरा में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। एम.पी. ट्रांसको के मुख्य वित्तीय अधिकारी मुकुल मेहरोत्रा ने बताया कि शिविर में पेंशनर्स को लाइव डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया समझाई गई। इससे उपस्थित पेंशनर्स को आधुनिक डिजिटल सुविधाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करने की सरल एवं त्वरित प्रक्रिया से अवगत कराना और उन्हें एक ही स्थान पर सहज सेवाएँ उपलब्ध कराना था।

धारा 126 के प्रकरणों में विद्युत उपभोक्ताओं को छूट प्राप्त करने का मौका

उपभोक्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन

भोपाल(नप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्ताओं के लिए धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन एक दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्लीक लिंक टैब में Rebate As lokadalat in section 126 पर क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कंपनी के portal.mpcz.in पोर्टल पर कंज्यूमर आईडी की प्रविष्टि करते ही उपभोक्ता को धारा-126 में दर्ज लंबित प्रकरण प्रदर्शित होगा। उपभोक्ता को लोक अदालत की तर्ज पर धारा-126 में छूट प्राप्त किए जाने हेतु उपभोक्ता के परिसर या अन्य परिसर पर संयोजन के विरूद्ध विद्युत देयक की बकाया राशि नहीं है तथा विचाराधीन प्रकरण पर धारा 127 के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है न ही निर्णित है सत्यापित कर सबमिट करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चयन कर भुगतान कर सकते हैं।

इसी प्रकार ऑफलाइन आवेदन के लिये उपभोक्ताओं के लिए नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र/जोन पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा।

विश्व हिंदी परिषद के सम्मेलन में आज डॉ. भार्गव का व्याख्यान

इंदौर। विश्व हिंदी परिषद की ओर से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में 22 नवंबर 2025 को 'पं दीनदयाल उपाध्यायः प्रकृति,संस्कृति और दर्शन' विषय पर रिटायर्ड आईएएस डॉ अशोक भार्गव का उद्बोधन होगा। डॉ भार्गव मध्यप्रदेश के कई जिलों में कलेक्टर रहें हैं और रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर भी रहे। पर्यावरण और भारतीय संस्कृति भी उनका लेखन कार्य प्रकाशित होता रहता है।

अच्छे व्यक्तियों को सदैव मिलता है सम्मान : राज्यपाल श्री पटेल

एकाग्रता और समर्पण से मिलती सफलता

राज्यपाल से मिले प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि हर समय, हर समाज में अच्छे व्यक्तियों का सदैव सम्मान होता है। संवेदनशीलता पूर्वक किए सेवा कार्यों से आत्मिक आनंद मिलता है। भौतिक सुविधाओं का सुख क्षणिक होता है। पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ सीखना ही भावी जीवन की सफलताओं का आधार है। प्रशिक्षण के दौरान छोटी सी चूक भविष्य की बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। राज्यपाल श्री पटेल शुक्रवार को राजभवन में आए आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी के प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी और अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रकृति के जीवों में सबसे शक्तिशाली मानव है, जिसे बुद्धि और वाणी के रूप में अद्वितीय शक्ति मिली है। इन शक्तियों के सार्थक उपयोग से व्यक्ति उतरोत्तर बेहतर बनता है। आवश्यकता, बुद्धि के सकारात्मक और वाणी के शालीन उपयोग की है। उन्होंने कहा कि भावी जीवन में सदैव सीखने और अनुभवों से समझने का भाव रहना चाहिए। महत्वपूर्ण उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान समाज के सबसे वंचित, पिछड़े और गरीब व्यक्तियों से ही मिलता है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवक सरकार और जनता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। सुशासन

का आधार होते हैं। सुशासन की प्राथमिक आवश्यकता है कि अधिकारी संवेदनशीलता, विवेक, न्यायोचित व्यवहार और तथ्यों के आधार पर निर्णय करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण वंचित, गरीब और पिछड़े व्यक्तियों, समुदायों की मदद और उत्थान के उद्देश्यों से होता है। योजना की मंशा के भाव, भावनाओं और हितग्राही की परिस्थितियों को समझे बिना उनके स्वरूप के निर्धारण और क्रियान्वयन से समस्याएं उत्पन्न होती है।

अमृत हरित महाअभियान के लिये संभागवार बैठकें

स्थानीय नर्सरियों को सुदृढ़ करने के निर्देश

भोपाल (नप्र)। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को वर्ष 2026 के लिये व्यापक पौधरोपण अभियान की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में संभागीय स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री संकेत भोंडवे 28 नवम्बर को सागर में अमृत हरित महाअभियान पर केन्द्रित बैठक में तैयार की गई कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे।

ग्वालियर में अभियान की हुई समीक्षा

ग्वालियर में पिछले दिनों नगरीय निकायों के अमृत हरित महाअभियान के नोडल अधिकारी और फील्ड स्टाफ की हुई बैठक में ग्वालियर और चंबल संभाग की तैयार की गई कार्ययोजना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद हुई कार्यशाला में अमृत मित्र महिलाओं को पौधों की सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग के 59 नगरीय निकायों में पिछले वर्ष 3 लाख 50 हजार विभिन्न किस्मों के पौधों का रोपण हुआ था। कार्यशाला में ग्वालियर नगर निगम आयुक्त श्री संघप्रिय ने वर्ष 2026 के लिये तैयार की जा रही कार्ययोजना की जानकारी दी। जबलपुर में 5 दिसम्बर को और इंदौर में 10 दिसम्बर को कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इन कार्यशालाओं में स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। नगरीय निकायों द्वारा वर्ष 2026 में सीवरेज, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओवरहेड टेंक के साथ जलसंरचनाओं के आस-पास की भूमि पर व्यापक पौधरोपण की तैयारी किये जाने के लिये कहा गया है। नगरीय निकायों को स्थानीय स्तर पर नर्सरियों को समृद्ध करने के लिये कहा गया है। इन बैठकों में वर्ष-2025 में लगाएं गए पौधों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की जा रही है।

धनखड़ ने किया संघ नेता की किताब का विमोचन

भोपाल (नप्र)। पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शुक्रवार को भोपाल पहुंचे। यहां वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मनमोहन वैद्य की पुस्तक 'हम और यह विश्व' का विमोचन किया। कार्यक्रम में मनमोहन वैद्य ने अपने संबोधन की शुरुआत में जगदीप धनखड़ को अपना अभिभावक कहा। वैद्य ने कहा एक घटना ने मेरे अंदर के लेखक को जाग्रत किया। संघ के तृतीय वर्ग के प्रशिक्षण वर्ग में प्रणब मुखर्जी को बुलाया था। वो संघ जॉइन नहीं करने वाले थे। उन्हें सिर्फ संबोधन देना था, लेकिन उनका बहुत विरोध हुआ। बेवजह विरोध देखकर मैंने लेखन की शुरुआत की।

रात में दिल्ली होंगे रवाना- दिल्ली से भोपाल पहुंचने के बाद धनखड़ सीधे एयरपोर्ट से राजभवन रवाना हुए। कार्यक्रम में वृंदावन के श्री आनंदम धाम आश्रम के पीठाधीश्वर रीतेश्वर जी महाराज और वरिष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि हैं।

सरकारी पैसों से वोट की खरीद-फरोख्त बंद करे भाजपा सरकार

चुनाव आयोग तत्काल हस्तक्षेप करे - कांग्रेस

भोपाल। आज मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव झा को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में सरकारी योजनाओं के माध्यम से खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर वोट खरीदे जा रहे हैं।

ज्ञापन सौंपने वाले कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, भोपाल शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया, शाबिस्ता जाकी, प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, अभिनव बरोलिया, पार्षद गुड्डू चौहान, मतदाता सूची पुनरीक्षण के प्रभारी ललित सेन, रमेश पांडे तथा निकेश चौहान शामिल रहे।

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि बिहार चुनाव के दौरान जीविका दीदी स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं 18 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को मिलाकर लगभग 130 करोड़ रुपये की राशि इज्जत धन के नाम से बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जबकि उस समय चुनाव आचार संहिता प्रभावी थी। प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की राशि देकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसी प्रकार महाराष्ट्र सहित अन्य भाजपा शासित प्रदेशों में भी केन्द्र की चुनाव आचार संहिता को खुली चुनौती देते हुए सरकारी पैसों से वोट प्रभावित किए जा रहे हैं।

प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पहले चुनाव की घोषणा से छह माह पूर्व तक सरकारों व राजनीतिक दलों पर नई घोषणाएँ करने पर सख्त रोक रहती थी, परंतु अब अवधि घटाकर तीन माह कर दी गई है, जिसका भाजपा सरकारें खुला दुरुपयोग कर रही हैं। मध्यप्रदेश में भी मई 2023 के चुनाव से पहले तत्कालीन भाजपा सरकार ने लाड़ली बहना योजना के नाम पर 1000 रुपये प्रतिमाह देकर चुनाव को प्रभावित किया था। यह सब लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना पर सीधा प्रहार है।

समृद्ध मध्यप्रदेश के लिये बनाएं अपनी पसंद का बजट : उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

बजट 2026-27 के लिये सरकार ने आम नागरिकों से मांगे सुझाव

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि विकसित मध्यप्रदेश@2047 के विजन को साकार करने में वित्तीय वर्ष 2026-27 बजट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें हर नागरिक की भूमिका होगी। बजट निर्माण में हर नागरिक की भागीदारी के लिये राज्य सरकार ने सभी से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा अनुसार नागरिकों, विशेषज्ञों और संगठनों के सुझावों से बजट को और अधिक व्यावहारिक तथा विकासोन्मुखी बनाया जाएगा। नागरिक अपने सुझाव MPMyGov पोर्टल, टोल फ्री नंबर 0755-2700800, ईमेल budget.mp@mp.gov.in तथा डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 18 दिसम्बर 2025 निर्धारित है।

बजट निर्माण की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। आम नागरिकों की अपेक्षाओं को बजट में शामिल किया जायेगा। बजट प्रक्रिया को जनभागीदारी आधारित, लोक हितैषी और भविष्य उन्मुख बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है।

अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार पर फोकस

मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश के वित्तीय प्रशासन का एक मजबूत ढांचा तैयार हो रहा है। इसके लिए अभी से एक आर्थिक नियोजन की तैयारी करना आवश्यक होगा। डेटा-आधारित वित्तीय रणनीति बनाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में निरंतर सुधार लाना प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को संसाधनों के कुशल प्रबंधन और कठोर वित्तीय अनुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

समृद्ध मध्यप्रदेश बनाने में दें सहयोग

विकसित मध्यप्रदेश@2047 के कई सेक्टर हैं जो आम नागरिकों के जीवन से सीधा जुड़े हैं। वर्ष 2047 तक प्रदेश को समृद्ध, संपन्न, सुखद और सांस्कृतिक समृद्ध बनाने के लिये प्रत्येक स्तर पर सभी नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है।

वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश देश में पर्यटन क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का प्रदेश बनाना है। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नम्बर एक प्रदेश बनना है। मध्यप्रदेश सांस्कृतिक समृद्धि आधारित अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। कौशल एवं प्रशिक्षण का अत्याधुनिक इको सिस्टम बनने के लिए प्रदेश तैयार हो रहा है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अगले वर्ष को कृषि आधारित उद्योगों को समर्पित वर्ष घोषित किया है। विगत कई वर्षों से प्रदेश की कृषि विकास दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, अगले 2 दशकों में मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश होगा। इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आदर्श स्थिति में होगी। औदयागिक निवेश का सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में चारों ओर दिखने लगेगा।

बनाएं अपने सपनों का नया मध्यप्रदेश

बजट प्रदेश की आर्थिक गति को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रदेश में शासन एवं इसकी संबद्ध संस्थाओं में एक लाख से अधिक पदों की पूर्ति का लक्ष्य भी इस बजट प्रक्रिया का हिस्सा है। MPMyGov प्लेटफॉर्म पर प्राप्त सभी सुझावों को बजट निर्माण में प्राथमिकता से शामिल किया जाएगा।